सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 279 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, गुरूवार 23 जुलाई 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

अतिथि शिक्षकों को बसों में भरकर ले गई पुलिस, देर रात टेंट उखाड़ा

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ अतिथि शिक्षकों के धरने पर देर रात पुलिस ने कार्रवाई की। हिंदी भवन के सामने पिछले 22 दिनों से चल रहे धरना स्थल से पुलिस ने टेंट हटाकर जब्त कर लिया। इसके बाद आज (गुरुवार) सुबह धरना स्थल पहुंचे करीब 50 अतिथि शिक्षकों को पुलिस बसों में बैठाकर ले गई। धरनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि कोई नया प्रदर्शनकारी आंदोलन में शामिल न हो सके। इससे पहले दिन में पुलिस ने धरना समाप्त करने की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बावजूद शिक्षक धरने पर डटे रहे, जिसके बाद देर रात यह कार्रवाई की गई। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी अतिथि शिक्षकों ने साफकहा कि उनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। शिक्षकों का कहना है कि वे फिर से धरना देने की कोशिश करेंगे और जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।

बीजेपी-कांग्रेस में टकराव, कांग्रेस के 12 नेताओं समेत अन्य पर एफआईआर

रायपुर। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शन का असर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस ने रायपुर में जमकर बवाल मचाया। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए वॉटर कैनन से पानी की बौछार करने के साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बीजेपी की ओर से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय घेराव के दौरान मचे बवाल में पुलिस ने कांग्रेस के 12 नामजद नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। खम्हारडीह थाना प्रभारी निरीक्षक भावेश कुमार गौतम की शिकायत पर कांग्रेसियों पर शासकीय कार्य में बांधा पहुंचाने, बल प्रयोग और कानून-व्यवस्था भंग करने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरीकेडिंग तोड़ने की कोशिश की।

पत्नी पर बसूले से हमला, पति को तीन साल का कठोर कारावास

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र में छठी कार्यक्रम के दौरान अपनी पत्नी पर बसूले से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने बरपारा धनगवां निवासी बुधराम उईके (40) को दोषसिद्ध पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 600 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कौशल सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

दुर्ग पुलिस की बड़ी उपलब्धि : डिजिटल एफआईआर लागू करने वाला बना पहला जिला

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। डिजीटल एफआईआर प्रणाली लागू करने की दिशा में दुर्ग पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदाय ई-साइन के माध्यम से थाना भिलाई नगर में प्रार्थी का प्रथम ई-साइन सफलतापूर्वक संपादित किया गया। प्रार्थी का ई-साइन भी सफलतापूर्वक प्रारंभ होने के साथ दुर्ग, छत्तीसगढ़ का पूर्णत: डिजिटल एफआईआर प्रणाली लागू करने वाला प्रथम जिला बन गया है।

शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी करेंगे ई-साइन, भिलाई नगर में सफल हुआ पहला ई-साइन

पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के थानों को प्रदाय किए गए ई-साइन के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली का क्रियान्वयन दुर्ग में किया जा रहा है। दुर्ग जिले के सभी विवेचक शत-प्रतिशत ई-साइन के माध्यम से एफआईआर की प्रक्रिया संपादित कर रहे हैं। इसके साथ ही दुर्ग छत्तीसगढ़ का प्रथम जिला बन गया जहां विवेचक व प्रार्थी दोनों के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से डिजिटल एफआईआर प्रक्रिया लागू कर दी गई है।

यह व्यवस्था एफआईआर पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, समयबद्ध एवं पेपरलेस बनाने के साथ-साथ डिजिटल अभिलेखों के प्रभावी संधारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दुर्ग पुलिस आधुनिक तकनीक के माध्यम से पारदर्शी, प्रभावी एवं नागरिक-केंद्रित पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर नवाचार एवं डिजिटल प्रणालियों के विस्तार हेतु प्रतिबद्ध है।

प्रदेश के थानों को मिले ई-पेन

दुर्ग पुलिस के अनुसार, पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के थानों को ई-पेन उपलब्ध कराए हैं। इन्हीं की मदद से एफआईआर पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। अब एफआईआर दर्ज करते समय विवेचक के साथ-साथ शिकायतकर्ता भी ई-साइन करेगा। इससे पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित और अधिक सुविधाजनक हो गई है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल एफआईआर प्रणाली से लोगों को बेहतर और आधुनिक सेवाएं मिलेंगी। रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा।

भिलाई में बड़ा हादसा : सेंट्रल एवेन्यू पर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, दो युवकों की मौत

■ भिलाई नगर थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस जांच शुरू

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। बीएसपी टाउनशिप के सेंट्रल एवेन्यू में गुरुवार तड़के सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। हादसा तड़के 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। कार सवार दोनों युवक काफी तेज रफ्तार में थे और सेक्टर-10 गुंडिचा मंडप के पास सड़क किनारे पेड़ से टकरा गए। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही भिलाई नगर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को मरच्यूरी पहुंचाया। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक सेक्टर-6 सड़क 35 के रहने वाले बताए जा रहे हैं। युवकों के नाम दीपक गुप्ता और कौशिक दास बताया जा रहा है। सुबह 4:00 बजे सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रही कार क्रमांक सीजी 07 एमबी 5986 पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार में सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नेहरू नगर से वापस लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार को कंट्रोल नहीं कर पाए और हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। दोनों युवकों के शवों को मरच्यूरी रवाना किया गया। वहीं हादसे की सूचना युवकों के परिजनों को दे दी गई है। आरटीओ के रिकार्ड के अनुसार सीजी 07 एमबी 5986 सड़क 46 सेक्टर -6 निवासी एस गौरी प्रसाद के नाम पर रजिस्टर्ड है। शुरुआती जांच में कार के भीतर शराब की बोतल व अन्य सामान मिला है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसे के समय कार कौन चला रहा था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ड्राइविंग सीट पर कौन था और दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार हादसे की एक संभावित वजह मानी जा रही है। फिलहाल भिलाई नगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

पुलिस, वन रक्षक और प्रहरी भर्ती में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण

■ साय कैबिनेट का बड़ा निर्णय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अग्निवीरो के लिए खुशखबरी है। बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अग्निवीर सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद् ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों - पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों को 10 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है।

सरकार ने छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। इस निर्णय से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा।

दुर्ग के घर में लगी भीषण आग: 4.30 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

■ दमकल की दो टीमों ने आसपास के घरों तक फैलने से रोकी लपटें

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। जिले के अंडा थाना क्षेत्र के ग्राम अछोटी में बुधवार रात एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। घटना की सूचना मिलते ही दुर्ग अग्निशमन विभाग की दो दमकल गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने करीब साढ़े चार घंटे तक लगातार राहत और बचाव अभियान चलाकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

यह घटना बुधवार रात करीब 8 बजे की है। आग रामचरण के मकान में लगी थी। स्थानीय लोगों ने घर से धुआं और आग की तेज लपटें निकलती देख तुरंत अग्निशमन कार्यालय दुर्ग को सूचना दी। सूचना मिलते ही विभाग ने बिना देरी किए दो दमकल टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया। दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचने तक आग काफी फैल चुकी थी। पूरे घर से तेज लपटें निकल रही थीं।

4 घंटे से ज्यादा चला रेस्क्यू

आग लगने के बाद आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत की गई। करीब 4 घंटे 30 मिनट तक आग बुझाने का प्रयास बाद दमकल टीम ने किया, जिसके बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। अग्निशमन विभाग के मुताबिक फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। हादसे में किसी व्यक्ति के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है।

आग के कारणों जांच जारी

जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी दिनेश राउटे ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को तत्काल रवाना किया गया था। कर्मचारियों ने समय रहते मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पा लिया। यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता, तो आसपास के मकान भी इसकी चपेट में आ सकते थे। टीम की सतर्कता और लगातार प्रयास से बड़ी घटना होने से टल गई। आग किन कारणों से लगी है, इसका पता लगाया जा रहा है।

पेपर लीक विवाद: पीएम मोदी बोले- दोषियों को जल्द सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने, मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों और अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री की ओर से यह घोषणा तब की गई है, जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में छात्रों-युवाओं का प्रदर्शन जारी है।

गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री का यह अहम कदम है।

संपादकीय

कचरे का संकट

कर्मियों व लोगों की सेहत-सुरक्षा जरूरी

यह हमारी व्यवस्था की विडंबना ही है कि सड़कों व सार्वजनिक स्थलों में पसरा कचरा हटाना हमारी प्राथमिकता नहीं बनता। यह कचरा केवल दिखने में ही बुरा नहीं लगता बल्कि कई तरह के रोगों को जन्म देकर सार्वजनिक संकट का कारक भी बन सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण सफाई का काम करने वाला वर्ग आर्थिक व सम्मान की दृष्टि से सबस ज्यादा उपेक्षित रहता है। कमोबेश पंजाब की सड़कों पर जमा कचरा यही संकट दर्शा रहा है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच घातक बीमारियां फैलने के खतरे को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की चेतावनी यह बताती है कि शहरी जीवन के लिये मूलभूत नागरिक सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। खासकर मानसून के सीजन में यदि कचरा नहीं उठाया जाता तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। बारिश में इस कचरे के बहने से नालियां जाम हो जाती हैं। वहीं पानी के स्रोत भी दूषित हो सकते हैं। साथ ही मच्छर,चूहे व कीट-पतंगे पनपने से बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट का राज्यभर की नागरिक संस्थाओं से रिपोर्ट मांगना और सरकार की जवाबदेही तय करना वक्त की जरूरत भी है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि नगर निकायों के अधिकारियों को जरूरी सेवाओं, विशेषकर लोगों की सेहत से सीधे जुड़ी सेवाओं के लिये आपातकालीन योजनाएं बनानी ही चाहिए। निस्संदेह, इस संकट को महज कानून व व्यवस्था के नजरिये से ही नहीं देखा जा सकता। निर्विवाद रूप से हमारे समाज में सफाई कर्मचारियों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इस अहम कार्य को हम अपेक्षित मान्यता नहीं देते। यह विडंबना ही है कि सफाई कर्मचारी लंबे समय से नौकरी की असुरक्षा, स्थायी होने में लगने वाली देरी, मिलने वाला कम वेतन और काम करने की खराब स्थितियों की शिकायत करते रहते हैं। शोचनीय स्थिति यह है तंत्र सफाई कर्मचारियों की मांगों को तब तक नजरअंदाज करता है, जब तक वे अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों में नहीं उतर जाते।

> “ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण सफाई का काम करने वाला वर्ग आर्थिक व सम्मान की दृष्टि से सबस ज्यादा उपेक्षित रहता है। कमोबेश पंजाब की सड़कों पर जमा कचरा यही संकट दर्शा रहा है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच घातक बीमारियां फैलने के खतरे को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की चेतावनी यह बताती है कि शहरी जीवन के लिये मूलभूत नागरिक सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। खासकर मानसून के सीजन में यदि कचरा नहीं उठाया जाता तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। बारिश में इस कचरे के बहने से नालियां जाम हो जाती हैं। वहीं पानी के स्रोत भी दूषित हो सकते हैं। साथ ही मच्छर,चूहे व कीट-पतंगे पनपने से बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

बहरहाल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सफाई कर्मचारियों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। लेकिन हड़ताल व स्वास्थ्य सेवाओं का ठप होना न तो लोगों के हित में है और न ही सफाईकर्मियों के हक में। भारत में हर रोज 1.7 लाख टन से ज्यादा ठोस कचरा विभिन्न नगरपालिकाओं के अंतर्गत पैदा होता है। लेकिन तीव्र गति से बढ़ते शहरीकरण के चलते नागरिक सेवाओं पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में इस चुनौती के मुकाबले के लिये आधुनिक तकनीक के साथ प्रोफेशनल तरीके से ठोस कचरे का निस्तारण होना चाहिए। साथ ही जरूरी है कि पर्याप्त स्टाफ मिले, सफाई के आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जाएं। इसके अलावा इस क्षेत्र में निरंतर निवेश बढ़ाया जाए। हमारे नीति-नियंताओं को सोचना चाहिए कि आपातकाल के समय की गई कोई भी कार्रवाई लंबी अवधि की योजना का विकल्प नहीं बन सकती। ऐसे में सरकार के अधिकारियों को तुरंत सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए। उनकी जायज मांगों को एक तय समय सीमा में हल करने की दिशा में अविलंब काम करना चाहिए। इसके अलावा आपातकालीन इंतजामों के जरिये साफ-सफाई से जुड़ी सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहनी चाहिए। निस्संदेह, किसी भी तरह के विवाद के चलते आम लोगों की सेहत को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। यह भी विडंबना ही है कि जब तक सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा जमा होना शुरू नहीं होता, तब तक अक्सर शहरों की सफाई को हल्के में ले लिया जाता है। निश्चित रूप से हाल ही में पंजाब में पैदा हुए गतिरोध से हमें सबक लेना चाहिए। बल्कि इस चुनौती के बीच साफ-सफाई को एक जरूरी जन सेवा के तौर पर मान्यता देने का उपक्रम करना चाहिए। हमारा प्रयास हो कि हम शहरों की सफाई के लिये बेहतर नियोजन करें। इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफाई के काम से जुड़े लोगों के कार्य का महत्व समझते हुए उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया जाए। नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

एक लाख से दो लाख: उद्यमी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं

चिराग पासवान

जब 2020 में कोविड-19 महामारी ने लोगों के जीवन और आजीविका पर बुरा असर डाला, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महसूस किया कि फिर से पूर्वस्थिति बहाल करने की प्रक्रिया केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे सबसे छोटे उत्पादकों और उद्यमों तक भी पहुँचना चाहिए, खासकर उन उद्यमों तक, जो भारत के गांवों और छोटे शहरों में कार्यरत हैं।

इस उद्देश्य के साथ, उस साल, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना शुरु की गई थी। इसकी शुरुआत खाद्य अर्थव्यवस्था के उस हिस्से के साथ हुई, जो लंबे समय तक औपचारिक वित्त और संस्थागत समर्थन से बाहर रहा था: सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, जो पहले ही उत्पादन व बिक्री कर रहे थे और कुछ लोगों को रोजगार दे रहे थे, लेकिन जिनके पास आगे बढ़ने के लिए आवश्यक पूंजी या मार्गदर्शन नहीं था। यह योजना उस विश्वास को प्रतिबिंबित करती है, जिसे प्रधानमंत्री लगातार मानते रहे हैं, कि भारत की वृद्धि इसके आधार से शुरू होनी चाहिए, यानि उन लोगों के बीच, जो अपने खुद के उद्यम शुरू करना चाहते हैं।

पीएमएफएमई के ऋण से जुड़े घटक के तहत अब तक दो लाख से अधिक मंजूरियां दी जा चुकी हैं। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पीछे वे उद्यमी हैं, जो औपचारिक ऋण-प्रणाली से जुड़े हैं और जिन्हें अपने उद्यम-निर्माण का असली मौका मिला है। यह जश्न मनाने लायक उपलब्धि है और उन लोगों का सम्मान करने का अवसर है, जिन्होंने इसे संभव बनाया है।

इनमें सबसे पहले व्यक्ति जमनालाल पाटीदार थे, जिनका आवेदन पीएमएफएमई के तहत सबसे पहले मंजूर किया गया था। 10वीं पास इस उद्यमी के पास खाद्य प्रसंस्करण का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन इन्होंने ?10 लाख के निवेश के साथ धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू की। इस योजना की मदद से उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन की सुविधा मिली और उनका विचार एक कामयाब व्यवसाय में बदल गया, जो आज पाँच से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है।

उसकी कहानी एक सरल बात बताती है। उद्यमिता केवल अच्छे परिवार या अच्छे शिक्षा प्राप्त लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने विचार को क्रियान्वित करने के लिए वित्त, तकनीक और सहायता प्राप्त कर सकता है। आम भारतीयों को उद्यम बनाने और दूसरों को रोजगार देने में सक्षम बनाकर, पीएमएफएमई योजना प्रधानमंत्री के उस विज़न को आगे बढ़ा रही है, जिसमें नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वाले में बदलने की बात कही गयी है।

भारत में लंबे समय से छोटे स्तर पर काम करने वाले लाखों कुशल उद्यमी मौजूद रहे हैं, जो विशिष्ट स्थानीय उत्पाद बनाते हैं। इनमें से कई लोगों के पास किफायती वित्त, आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता प्रमाणन और संगठित बाजार तक पहुँच की कमी थी। यह योजना ऋण से जुड़ी सहायता, क्षमता निर्माण, साझा अवसंरचना, ब्रांडिंग और बाजार पहुँच के जरिये इन कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना था, ताकि उनके पास आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर हो।

इस बदलाव में महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही है। ऋण से जुड़ी दो लाख मंजूरियों में से लगभग 44 प्रतिशत का

लाभ महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को मिला है, जबकि चार लाख से अधिक स्व-सहायता समूह के सदस्यों ने अपने व्यवसाय को मजबूत और उन्नत करने के लिए शुरुआती पूंजी प्राप्त की है। पूरी योजना से 20,300 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है और लगभग छह लाख लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। 75,000 से अधिक इकाइयाँ उद्यम पंजीकरण और एफएसएसएआई व जीएसटी के तहत अनुपालन के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुकी हैं। कई महिलाओं के लिए इसका मतलब है, घर या समुदाय में अभ्यास किये जाने वाले हुनर को ऐसे मान्यता प्राप्त उद्यमों में बदलना, जहाँ उन्हें वित्त, तकनीक और बड़े बाज़ारों तक पहुँच मिल सके। इस बदलाव में अन्य महिलाओं को मदद करना अगले चरण की प्राथमिकता होनी चाहिए।

इनमें से प्रत्येक संख्या के पीछे एक बड़ा लाभ छिपा है। एक कामकाजी उद्यमी किसान की उपज खरीदता है, हर फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है और अधिक मूल्य वहीं रखता है जहां इसे बनाया गया है। एक स्थानीय फसल ब्रांडेड उत्पाद बन जाती है। एक घरेलू कौशल स्थायी रोजगार बन जाता है। समय के साथ, एक जिले की पहचान उसके द्वारा बनाई गयी चीज़ों से होने लगती है। व्यावहारिक तौर पर यही वोकल फॉर लोकल है, एक समय में एक उद्यम।

पीएमएफएमई के तहत दो लाखवीं मंजूरी रांची के इंदरजीत सिंह को मिली, जो एक बेकरी बना रहे हैं और सपना देखते हैं कि उनके केक और पेस्ट्री एक दिन पूरे झारखंड में मशहूर होंगे। पूर्व के पाटीदार की तरह, वे छोटे उद्यम और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ शुरुआत कर रहे हैं और उन्हें योजना का सहारा भी मिल रहा है। वे पहली पीढ़ी के हजारों उद्यमियों में से एक हैं, जिन्हें पीएमएफएमई योजना पहली मंजूरी से एक सफल उद्यम तक पहुंचा रही है। अगर पाटीदार दिखाते हैं कि यह यात्रा कितनी दूर तक जा सकती है, तो सिंह दिखाते हैं कि यह अभी और गति पकड़ रही है।

आगे के रास्ते का यही रूप है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के लिए औपचारिक ऋण को सुविधाजनक बनाना पहला काम था, और मुश्किल लेकिन ज्यादा संतोषजनक काम यह है कि हर मंजूरी को वास्तव में दिए गए ऋण में बदलना, और हर ऋण से एक ऐसा व्यवसाय बनाना, जो कारोबार करे और लंबे समय तक चलता रहे। मंजूरी से दरवाजा खुलता है; हमारा काम हर उद्यमी को उस दरवाजे से गुजरने में मदद करना है, ताकि वे कुछ ऐसा बनाएं, जो लंबे समय तक चले।

पीएमएफएमई के अगले चरण की दिशा यही होनी चाहिए। हम होनहार उद्यमों तक तेज़ी से ऋण पहुँचाएँगे, बेहतर तकनीक और पैकेजिंग अपनाने में उनकी मदद करेंगे, बाज़ार तक उनकी पहुँच का विस्तार करेंगे और इनमें से बहुत से उद्यमियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचने के लिए तैयार करेंगे। हम उद्यमियों के साथ मंजूरी के केवल पहले ही नहीं, बल्कि मंजूरी के बाद भी खड़े रहेंगे, उन्हें लगातार ऐसा सहयोग देंगे, जिससे उनका पहला ऋण स्थायी आजीविका का एक ज़रिया बन जाए।

कुल मिलाकर, ये दो लाख मंजूरियां प्रशासनिक उपलब्धि से कहीं ज़्यादा हैं। हर ऐसा उद्यम, जो जड़ें जमा लेता है, अपने आस-पास की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। यह पास के खेतों से खरीदारी करता है, घर के पास आय सृजित करता है और महिलाओं और युवा भारतीयों को खुद का व्यवसाय शुरू करने का आत्मविश्वास देता है।

जब हम पाटीदार की धनिया इकाई को देखते हैं, तो सबक सरल है। पीएमएफएमई के तहत पहली मंजूरी एक ऐसे व्यक्ति को मिली, जिसके पास न तो स्थापित फैक्टरी थी और न ही कोई विशेष डिग्री। उनके पास केवल एक विचार था और काम करने की इच्छा थी और योजना ने उन्हें पहुँच की सुविधा दी। दो लाख मंजूरियों के बाद, ये अवसर अब पूरे देश के उद्यमियों तक पहुँच चुके हैं। अब हमारा काम है कि हम और अधिक लोगों को ऐसे व्यवसाय बनाने में मदद करें, जो चलते रहें, दूसरों को रोजगार दें और वहीं मूल्य बनाएं, जहां से उन्होंने शुरू किया है।

(लेखक केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं)

मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर बंटवारा

डॉ. सुधीर कुमार

आज के दौर में जब संयुक्त परिवार सिमट रहे हैं और भौतिकवाद हावी हो रहा है, यह फैसला एक संजीवनी का कार्य करता है। यह कानून हमें याद दिलाता है कि परिवार कोई कानूनी अनुबंध नहीं, बल्कि विश्वास और साझा दायित्वों का समूह है। संपत्ति के बंटवारे के समय 'न्याय' केवल कागजी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर भी होना चाहिए।

क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जो ज़मीन हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है, वह वास्तव में किसकी है? क्या वह केवल कागजों पर दर्ज हमारी एक निजी संपत्ति है जिसे हम जब चाहें, जैसे चाहें बेच दें? या फिर, उस मिट्टी के कण-कण पर हमारे पूरे परिवार, हमारे भाई-बहनों और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी कोई नैतिक और कानूनी हक है?

अक्सर गांवों, कस्बों और यहां तक कि शहरों में भी हमने देखा है कि ज़मीन के टुकड़े को लेकर घर के रिश्ते कैसे बिखर जाते हैं। किसी ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बिना परिवार से पूछे किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दी, और बस इसी एक फैसले से सालों-साल चलने वाली कलह की नींव पड़ गई। भाई-भाई से अलग हो गया, संयुक्त परिवार टूट गए और जो ज़मीन कभी समृद्धि का प्रतीक थी, वह कड़वाहट और अदालती मुकदमों की जड़ बन गई।

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 'महिंदर और अन्य बनाम पूरन सिंह' (14 जुलाई, 2026) मामले में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो भारत के हर उस परिवार के लिए एक 'सुरक्षा कवच' बन गया है, जिसके पास खेती की ज़मीन है। यह फैसला केवल कानूनी किताबों की कोई सूखी शब्दावली नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों की सामाजिक एकता को बचाने की कोशिश है, जिनकी जड़ें आज भी अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। यह कानूनी संघर्ष निचली अदालतों से शुरू हुआ था। विवाद का मुख्य मुद्दा बहुत सरल लेकिन गहरा था : क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22, खेती की ज़मीन पर भी लागू होती है? निचली अदालतों में एक लंबा तर्क चला कि खेती की ज़मीन आम संपत्तियों से अलग होती है। कुछ लोगों का कहना था कि यह आजीविका का साधन है, इसलिए इस पर मालिक का पूरा नियंत्रण होना चाहिए और उत्तराधिकार के सामान्य कानून इस पर लागू नहीं होने चाहिए।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम शंकाओं को एक झटके में खत्म कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून की नज़र में पुश्तैनी संपत्ति का स्वरूप नहीं बदलता। चाहे वह रहने का घर हो या खेती का खेत, यदि वह विरासत में मिली है, तो उसके प्रति कानूनी दायित्व समान हैं। कोर्ट ने यह संदेश दिया कि ज़मीन की प्रकृति बदल सकती है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी का स्वरूप नहीं।

सरल शब्दों में कहें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 का मतलब है- 'परिवार का पहला हक'। यह धारा कहती है कि यदि कोई वारिस विरासत में मिली संपत्ति का अपना हिस्सा बेचना चाहता है, तो वह सीधे किसी अनजान व्यक्ति या बाहरी खरीदार के पास नहीं जा सकता। इसे 'प्रिएम्पशन का अधिकार' कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बाहरी व्यक्ति को ज़मीन बेचने की स्वतंत्रता केवल तभी मिलती है जब परिवार का कोई भी सदस्य उसे खरीदने में रुचि न रखे या असमर्थ हो। यह कानूनी प्रावधान परिवार की पुश्तैनी विरासत को बाहरी हस्तक्षेप से बचाकर उसकी सामाजिक एकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है।

यूरोप के जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में खेती की ज़मीन को 'अविभाज्य इकाई' मानकर कड़े कानूनों के ज़रिए उसे परिवार के भीतर ही सुरक्षित रखा जाता है, ताकि पुश्तैनी परंपराएं बनी रहें। इसके विपरीत, अमेरिका में व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है और ज़मीन बेचने की पूरी आज़ादी है, लेकिन वहां भी संपन्न परिवार अपनी विरासत को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए 'फैमिली ट्रस्ट' और 'कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स' जैसी कानूनी व्यवस्थाओं का समझदारी से उपयोग करते हैं। भारत का कानून इन दोनों के बीच का एक संतुलन है। हम व्यक्ति की आज़ादी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन परिवार और समाज की एकता को भी बहुत महत्व देते हैं। यह भारतीय कानून की खूबी है कि वह हमें व्यक्तिगत अधिकार तो देता है, लेकिन साथ ही हमें यह याद दिलाता है कि हम एक सामाजिक इकाई का हिस्सा हैं। यह हमें दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले एक अधिक मानवीय चेहरा प्रदान करता है, जो रिश्तों को सिर्फ पैसे से ऊपर रखकर देखता है।

इस तरह, यह कानून न केवल विवादों को जन्म लेने से रोकता है, बल्कि परिवार के भीतर आपसी संवाद और रिश्तों की मजबूती को भी अनिवार्य बनाता है। नि:संदेह, ज़मीन का संरक्षण केवल संपत्ति का अधिकार नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनकी जड़ों से जोड़े रखने का एक पुनीत कर्तव्य है। यह कानून हमें याद दिलाता है कि कानून की असली सार्थकता तब सिद्ध होती है, जब वह न्याय प्रदान करने के साथ-साथ हमारी सामाजिक जड़ों को भी सींचता रहे।

आज के दौर में जब संयुक्त परिवार सिमट रहे हैं और भौतिकवाद हावी हो रहा है, यह फैसला एक संजीवनी का कार्य करता है। यह कानून हमें याद दिलाता है कि परिवार कोई कानूनी अनुबंध नहीं, बल्कि विश्वास और साझा दायित्वों का समूह है। संपत्ति के बंटवारे के समय 'न्याय' केवल कागजी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर भी होना चाहिए।

अगली बार जब आप अपने पुश्तैनी खेतों की मेड़ पर खड़े हों, तो याद रखिएगा कि वह ज़मीन मात्र मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार का सांझा इतिहास है। यदि अब आपसे कोई कहे कि 'मेरी ज़मीन, मैं किसी को भी बेचूं,' तो उन्हें धारा 22 की यह सरल सीख अवश्य याद दिलाइए 'कानून के अनुसार, पहला हक घर का, बाद में बाहर का; पहले परिवार को पूछिए, फिर बाहर देखिये!' यह कानून न केवल ज़मीन को सुरक्षित रखेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बीच रिश्तों की डोर को भी और मज़बूत करेगा।

लेखक कुरुक्षेत्र वि.वि. के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।

लोकतंत्र में सख्ती नहीं, उदार संवाद उपयोगी

विश्वनाथ सचदेव

यह भी समझना ज़रूरी है कि हमारा आज का युवा सिर्फ हंगामा खड़ा करने में विश्वास नहीं करता, वह सूरत बदलने के लिए बेचैन है। इससे पहले कि उसका आक्रोश हताशा में बदल जाए, कुछ नहीं, बहुत कुछ सकारात्मक करने की आवश्यकता है। सरकार कब जागेगी?

वह मां अपनी तेरह-चौदह साल की बच्ची को लेकर राजधानी दिल्ली के 'प्रदर्शन-स्थल' जंतर-मंतर में आई थी। एक पत्रकार ने जिज्ञासा की तो उस मां ने कहा था, 'मैं अपनी बेटी को एक वास्तविकता से परिचित कराने लाई हूं—कल उसे भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी।'

वह मां अकेली नहीं थी, जो अपनी संतान के बारे में इस तरह सोच रही थी। और वह बच्ची भी अकेली नहीं थी, जो अपने भीतर संघर्ष का एक जज़्बा लेकर वहां पहुंची थी। उस दिन, जब सड़क से संसद तक पहुंचने की एक होड़-सी लगी थी युवाओं में, तो यह जज़्बा अपने पूरे उफान पर था। हां, उस दिन वहां राजधानी दिल्ली के ही नहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों से भी हजारों 'कॉकरोच' इकट्ठे हुए थे। ये 'कॉकरोच' पिछले लगभग एक माह से अधिक समय से अपने अधिकारों के लिए और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए जंतर-मंतर पर बैठकर संघर्ष कर रहे थे। इस शांतिपूर्ण संघर्ष में कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कारगर अस्त्र—अनशन को अपना हथियार बनाया था। लद्दाख से आए सोनम वांगचुक का नेतृत्व मिला था इन युवाओं को।

एक मांग थी इन सबकी—देश की शिक्षा-व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाने वाली सरकार की नीतियों में बदलाव चाहते थे वे। देश का शिक्षामंत्री इन नीतियों का प्रतीक बना और देश के युवा यह मांग कर रहे थे कि वे स्थिति की जवाबदेही स्वीकार करें और अपने पद से इस्तीफा दें। पर देश की सरकार को यह स्वीकार नहीं था। ये युवा 6 जून से धरना दे रहे थे। हैरानी की बात यह है कि सरकार को न धरने की परवाह थी और न ही भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों की। शायद सरकार यह मानकर चल रही थी कि वे प्रदर्शनकारी थक जाएंगे और आंदोलन धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि यही सरकार की सोच थी, तो वह गलत थी।

सही क्या था, यह सरकार और देश ने संसद के मानसून अधिवेशन के पहले दिन देखा। हजारों की संख्या में देश के छात्र-युवा सरकार को यह दिखाने के लिए एकत्र हुए थे कि 'नीट' जैसी परीक्षाओं में हुए घोटालों से वे अपने भविष्य को अंधकारमय पा रहे हैं। देखा जाए तो यह आंदोलन युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई है। सरकार ने इसे बहुत हल्के में लिया था। हो सकता है, कल सरकार की यह असंवेदनशीलता युवाओं को थका दे, पर यह सवाल अपनी जगह बना रहेगा कि जनतांत्रिक व्यवस्था में कोई सरकार अपने ही युवाओं के प्रति इस तरह का रवैया कैसे अपना सकती है?

हैरानी की बात यह भी है कि एक महीने से भी अधिक समय से चल रहे इस आंदोलन के प्रति हमारे मुख्यधारा के मीडिया ने भी लंबे समय तक उसे वह महत्व नहीं दिया, जो दिया जाना चाहिए था। हां, संसद तक पहुंचने की कूच वाले दिन हमारा मीडिया ज़रूर कुछ सक्रिय हुआ और तब देश को पता चला कि युवाओं का आक्रोश सचमुच उफान पर था।

संयोग की बात है कि जब राजधानी दिल्ली में देश के युवा अपनी व्यथा का प्रदर्शन कर रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे, तभी हमारे युवा वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की खोज की कहानी में अपना योगदान दर्ज करवाया। प्रधानमंत्री ने इन युवा प्रतिभाओं को बधाई देते हुए देश की युवा शक्ति की उपलब्धियों और संभावनाओं का बखान किया। प्रशंसा के पात्र हैं हमारे ये युवा वैज्ञानिक, पर उन युवाओं पर प्रधानमंत्री की निगाह क्यों नहीं गई, जो राजधानी में संसद के दरवाजे तक पहुंचकर अपनी पीड़ा उन तक पहुंचाना चाहते थे?

जब युवाओं की टोलियां संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं, तो एक तरफ संसद भवन के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और दूसरी ओर लाठियों तथा आंसू गैस के गोलों से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। मीडिया की सहायता से सारे देश ने राजधानी की सड़कों पर छात्रों-युवाओं पर पुलिस की मार के दृश्य देखे। लाठीचार्ज में सैकड़ों छात्र-युवा घायल हो गए। पुलिस की ओर से इस हंगामे में घायल पुलिस कर्मियों की संख्या भी बताई गई। नहीं होना चाहिए था यह—न छात्र घायल होने चाहिए थे, न पुलिस वाले। पर सवाल, जो पूछा जाना चाहिए, वह यह है कि यह स्थिति क्यों आई?

स्थिति के इस स्तर तक पहुंचने के बाद सरकार की ओर से युवाओं को बातचीत के लिए बुलाया गया। यह काम पहले क्यों नहीं हो सकता था? जनतंत्र में लाठी नहीं, संवाद हथियार होता है। हैरानी की बात है कि इस सारे हंगामे के दौरान सरकार को न सड़कों पर नारे लगाते युवा दिखे और न ही भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक और उनके युवा साथी। हैरानी तो इस बात की भी है कि सरकार की ओर से यह कहना ज़रूरी समझा गया कि आंदोलनकारियों ने पहली बार बातचीत की पेशकश की है। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता था कि वह आंदोलन कर रहे युवाओं तक पहुंचकर उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करती? क्या ऐसा करने से सरकार की इज्जत घट जाती? इस सारे प्रकरण में जो कुछ हुआ है, वह सरकार की असंवेदनशीलता को ही उजागर करता है। 'नीट' जैसी परीक्षाओं में हुई धांधली पहली बार हुई घटना नहीं है। अक्सर इस तरह के घोटाले सामने आते रहे हैं और अक्सर उनकी अनदेखी की जाती रही है। यह सही है कि इस बार 'नीट' की परीक्षा फिर से हो गई और माना जा सकता है कि सब ठीक हो गया है। पर यह तो स्वीकारना ही होगा कि हमारी शिक्षा-प्रणाली में कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है, और इस गड़बड़ी के लिए किसी न किसी को अपना उत्तरदायित्व मानना ही होगा। बीस से अधिक छात्रों की आत्महत्या किसी भी एक मंत्री के इस्तीफे से कहीं अधिक गंभीर बात है। अब यदि 'कॉकरोच' कहे जाने वाले युवा शिक्षामंत्री के साथ-साथ प्रधानमंत्री के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो उसका कारण भी स्थिति की गंभीरता को सरकार द्वारा न समझना ही होगा।

बहरहाल, छात्रों और युवाओं ने इस प्रकरण में अब तक सहनशीलता का ही परिचय दिया है। यह भी संभव है कि सरकार के अड़ियल रुख के चलते निकट भविष्य में यह आंदोलन समाप्त भी हो जाए। पर युवा पीढ़ी में जो पीड़ा और आक्रोश दिखाई दिया है, वह किसी भी उत्तरदायी सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। इस बात को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि कितनी भी कोशिश कर लें, पर 'कॉकरोच' एक ऐसी प्रजाति है, जो खत्म नहीं की जा सकी है। पहले समस्या को समझना ज़रूरी है, और यही कोशिश वे नहीं कर रहे, जिनके कंधों पर समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने की जिम्मेदारी है। सवाल सिर्फशिक्षा-प्रणाली में सुधार का नहीं, गरीबी, महंगाई और बेरोज़गारी जैसी उन समस्याओं को सुलझाने का भी है, जो आज के युवाओं को परेशान कर रही हैं।

जंतर-मंतर पर जो कुछ हुआ और संसद भवन तक पहुंचने की युवा आंदोलनकारियों की कोशिशें इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि देश की युवा पीढ़ी की पीड़ा और आक्रोश को समझने की ईमानदार कोशिश नहीं हो रही। बीस छात्रों की आत्महत्या किसी भी सरकार को हिलाने की ताकत रखती है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह भी समझना ज़रूरी है कि हमारा आज का युवा सिर्फ हंगामा खड़ा करने में विश्वास नहीं करता, वह सूरत बदलने के लिए बेचैन है। इससे पहले कि उसका आक्रोश हताशा में बदल जाए, कुछ नहीं, बहुत कुछ सकारात्मक करने की आवश्यकता है। सरकार कब जागेगी?

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

संयंत्र के एसएमएस-3 में नए हॉट मेटल लैडल प्रीहीटर एवं वैकल्पिक सीओजी लाइन की सफल कमीशनिंग

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप-3 (एसएमएस-3) में पूर्णतः इन-हाउस संसाधनों से विकसित नए हॉट मेटल (एचएम) लैडल प्रीहीटर एवं वैकल्पिक कोक ओवन गैस हेडर लाइन की सफलतापूर्वक कमीशनिंग की गई। यह तकनीकी उपलब्धि उत्पादन क्षमता, बेहतर परिचालन तथा सुरक्षा मानकों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस परियोजना के माध्यम से रखरखाव कार्यों के दौरान भी उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ संयंत्र की उपलब्धता एवं कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

परियोजना के अंतर्गत एसएमएस-3 में दो महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार किए गए हैं। प्रथम, समर्पित डीएन-350 हेडर लाइन एवं नए हॉट मेटल लैडल प्रीहीटर की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से लैडल बे एवं नए प्रीहीटर को निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इससे लैडल को कम समय में तैयार करने की क्षमता बढ़ी है तथा

परिचालन बेहतर हुआ है। द्वितीय, वैकल्पिक सीओजी हेडर लाइन विकसित की गई है, जो लैडल ड्रायर सर्किट को निरंतर एवं स्थिर गैस आपूर्ति उपलब्ध कराती है। इससे प्रतिदिन निर्धारित उत्पादन लक्ष्य के अनुरूप आवश्यक संख्या में तैयार लैडल उपलब्ध रहेंगे। नई ड्यूल-हेडर प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी रेडंडेंसी है। अब लैडल ड्रायर सर्किट के नियमित अनुरक्षण के दौरान भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। इससे अनावश्यक डाउनटाइम में कमी आएगी तथा संयंत्र की उत्पादकता, उपलब्धता एवं परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

यह परियोजना भिलाई इस्पात संयंत्र की इन-हाउस इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी दक्षता एवं नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है। परियोजना की संकल्पना से लेकर सफल क्रियान्वयन तक का कार्य मुख्य महाप्रबंधक त्रिभुवन बैठा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस कार्य में महाप्रबंधक पी. के. अग्रवाल, महाप्रबंधक (मेंटेनेंस) पी. के. सतपथी, महाप्रबंधक (मैकेनिकल) संजीव कुमार मिश्रा, कन्वर्टर मैकेनिकल टीम से उप महाप्रबंधक राकेश वृष्णवंशी एवं वरिष्ठ प्रबंधक चंदन चतुर्वेदी तथा कन्वर्टर इलेक्ट्रिकल टीम से उप महाप्रबंधक रजत सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

प्रमुख खबरें

स्वैच्छिक रक्तदान अभियान को लेकर 25 जुलाई को कला मंदिर में बैठक आयोजित

दुर्ग। इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी दुर्ग द्वारा जिला चिकित्सालय में संचालित ब्लड बैंक में रक्त की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने और नियमित रक्तदान शिविरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे कला मंदिर, सिविक सेंटर, भिलाई में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष अभिजीत सिंह करेंगे। बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाज प्रमुखों, शैक्षणिक संस्थानों, पुलिस एवं अर्धसैनिक बल, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघ, औद्योगिक संस्थानों, राजनीतिक दलों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

सी.एम. हेल्पलाईन 1076 में की गई शिकायत पर आबकारी विभाग की कार्यवाही

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार सी.एम.पोर्टल हेल्प लाईन नम्बर 1076 में प्राप्त शिकायत अनुसार विगत 21 जुलाई 2026 को आबकारी विभाग वृत-दुर्ग आंतरिक उत्तर के द्वारा रात्रि 8:00 बजे त्वरित विधिवत कार्यवाही कर आरोपी जितेन्द्र गायकवाड़ निवासी अंजोरा ढाबा द्वारा 42 नग देशी मदिरा मसाला पाव कुल मात्रा 07.560 बल्क लीटर मदिरा को परिवहन करते पाये जाने पर उक्त मदिरा को जप्त कर प्रकरण विवेचना में लिया गया हैं। बिना परिमिट के आरोपी के कब्जे से 42 नग देशी मदिरा मसाला पाव पाए जाने एवं आरोपी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2) का उल्लघंन किये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। इस प्रकरण की विवेचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी, सुशीला साहू द्वारा की जा रही है। इस प्रकरण में आबकारी उप निरीक्षक रोहित वर्मा, आबकारी मुख्य आरक्षक अशोक वर्मा आबकारी आरक्षक रवि शंकर एवं चंद्रेश्वर मरकाम, ड्राइवर धनराज खरे का योगदान रहा।

जिले में अनुविभागीय दण्डाधिकारियों की नियुक्ति

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन पदस्थापना की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवीन अनुविभागीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसके तहत महेश सिंह राजपूत, संयुक्त कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी दुर्ग का दायित्व सौंपा गया है। लवकेश कुमार ध्रुव, संयुक्त कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी धमधा एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमधा के पद पर पदस्थ किया गया है। इसी क्रम में उत्तम कुमार ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी पाटन एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी पाटन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं प्रकाश सोनी, डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिलाई-3 एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिलाई-3 का नवीन प्रभार प्रदान किया गया है।

स्कूल रिकॉर्ड में जाति संशोधन की मांग अभिभावक ने दिया जनदर्शन में आवेदन

पट्टा में नाम परिवर्तन नहीं होने से योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अपर कलेक्टर सिल्ली थॉमस भी उपस्थित थीं।

जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 109 आवेदन प्राप्त हुए।

खुर्सीपार भिलाई निवासी अभिभावक ने अपनी पुत्री के स्कूल के दाखिल-खारिज रिकॉर्ड में दर्ज जाति के स्थान पर वास्तविक जाति दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने बताया गया है कि पहली कक्षा में प्रवेश के समय जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण स्कूल रिकॉर्ड में त्रुटिवश जाति दर्ज हो गया था। बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। स्कूल रिकॉर्ड में संशोधन नहीं होने पर भविष्य में छात्रवृत्ति, आरक्षण एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है।

इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम थनौद के किसानों ने भारतमाला सड़क निर्माण से फसल नुकसान की शिकायत की। किसानों ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान उनकी कृषि भूमि की मेड़ें समतल कर दी गईं, बाड़ और पोल हटा दिए गए तथा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि घेर ली गई, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पहली ही बारिश में खेतों का कटाव हुआ, मुरुम और मलबा खेतों में भर गया जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने उचित जल निकासी की व्यवस्था कराने, प्रभावित भूमि का सुधार कराने व मुआवजे की मांग की। इस पर कलेक्टर ने एनएचएआई को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

वैशाली नगर निवासी ने जनदर्शन में आवेदन देकर अपने आवासीय पट्टे में नाम परिवर्तन कराने की मांग की है। आवेदक ने बताया कि घर का पट्टा उनके बड़े भाई के नाम पर है। उनके बड़े भाई का वर्ष 2022 में निधन हो गया। इसके बाद भी पट्टा उनके नाम पर दर्ज नहीं हो सका है। नाम परिवर्तन नहीं होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

भव्य सावन मेले की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार सांस्कृतिक समिति की बैठक में बनी कार्ययोजना

दुर्ग। नगर पालिक निगम, महापौर अलका बाघमार के मार्गदर्शन में सांस्कृतिक पर्यटन, मनोरंजन एवं विरासत संरक्षण समिति की प्रभारी हर्षिका संभव जैन की अध्यक्षता में आगामी भव्य सावन मेला की तैयारियों को लेकर समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन मेले को अधिक भव्य, आकर्षक एवं जनसहभागिता से परिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में मेले के सफल आयोजन के लिए विभिन्न सांस्कृतिक, पारंपरिक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई।

समिति ने निर्णय लिया कि सावन मेले के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन कर स्थानीय प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही कार्यक्रमों की तिथि, आयोजन स्थल, प्रतिभागियों के पंजीयन एवं व्यवस्थाओं को लेकर शीघ्र ही विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

बैठक में पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं में फुगड़ी, रस्सीकूद, दौड़, रस्साकशी, कंची दौड़, मटका फोड़ एवं दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करने पर सहमति बनी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरसा, ठेठरी-खुर्मी, फरा, चीला जैसे पारंपरिक व्यंजनों की प्रतियोगिता, छत्तीसगढ़ी वेशभूषा प्रतियोगिता, छत्तीसगढ़ी मॉडलिंग, गायन प्रतियोगिता तथा रंगारंग छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी चर्चा की गई।

प्रभारी हर्षिका संभव जैन ने कहा कि सावन मेला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी लोक संस्कृति, परंपराओं और विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों से आयोजन को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय एवं सक्रिय सहभागिता के साथ कार्य करने का आग्रह किया।

दुर्ग में 25 से 29 जुलाई तक होगा पाँच दिवसीय कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की तैयारियों की समीक्षा

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में 22 जुलाई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के कार्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जिसमें जिले के सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पैरालीगल वॉलंटियर्स की भूमिका को और अधिक सशक्त, संगठित तथा जनसेवा केन्द्रित बनाना था, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सेवाओं की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित की जा सके। बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा कि विधिक सेवा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होगा, जब न्याय की पहुँच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरल, सुलभ एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी पैरा लीगल वॉलंटियर्स को नए उत्साह, नई कार्यशैली एवं नई जिम्मेदारियों के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पैरालीगल वॉलंटियर्स न्यायपालिका और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी से ही विधिक सहायता, जनजागरूकता एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुँचाया जा सकता है।

बैठक के दौरान मुख्य रूप से 25 जुलाई से 29 जुलाई, 2026 तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, दुर्ग के चतुर्थ तल में स्थित नवीन सभागार में आयोजित होने वाले पाँच दिवसीय कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष चर्चा की गई। सचिव द्वारा बताया गया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयनित पाँच ग्रामों कुथरेल, निकुम, घुघसीडीह, अरसनारा एवं ननकट्टी के सामुदायिक मध्यस्थ भाग लेंगे, जिन्हें विवादों के सौहार्दपूर्ण एवं वैकल्पिक समाधान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित सामुदायिक मध्यस्थता योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कृषि तालाब से बदली ममता चंद्राकर के खेत की तस्वीर

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन की परिसंपत्ति बनी सिंचाई, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का आधार

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत निर्मित परिसंपत्तियां केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आजीविका को स्थायी आधार भी प्रदान कर रही हैं। ग्राम पंचायत अंडा की हितग्राही ममता चंद्राकर एवं मनोज चंद्राकर इसका प्रेरणादायक उदाहरण हैं। उनके खेत में मनरेगा के अंतर्गत निर्मित कृषि तालाब ने खेती की तस्वीर ही बदल दी है। ग्राम पंचायत अंडा मुख्यत: कृषि प्रधान गांव है, जहां अधिकांश परिवार खेती और कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं। वर्षों से बारिश पर आधारित खेती और लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण किसानों को सिंचाई के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ममता चंद्राकर का परिवार भी इसी समस्या से जूझ रहा था। खेत में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण फसल उत्पादन सीमित रहता था और परिवार की आय भी प्रभावित होती थी। बताया गया कि कृषि तालाब वर्षा जल संरक्षण का प्रभावी माध्यम है, जिससे सिंचाई सुविधा बढ़ने के साथ-साथ मत्स्य पालन और अतिरिक्त फसल उत्पादन की संभावनाएं भी विकसित होती हैं। यह जानकारी ममता चंद्राकर के लिए उम्मीद की नई किरण बनी। उन्होंने अपने खेत में कृषि तालाब निर्माण के लिए आवेदन किया, जिसे ग्राम सभा की अनुशंसा पर स्वीकृति मिल गई।

रोजगार सहायक भूपेन्द्र चंद्राकर के अनुसार, वर्ष 2025-26 में इस कार्य को 2.99 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई। इसमें 2.79 लाख मजदूरी तथा 0.20 लाख सामग्री मद का प्रावधान था। कार्य 27 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुआ और निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किया गया। निर्माण कार्य के दौरान 1073 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ, जिससे स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। वहीं तकनीकी सहायक यमन बघेल ने बताया कि कार्य प्रारंभ होने से पहले स्थल चयन और ले-आउट तैयार किया गया।

इसके बाद वैज्ञानिक तरीके से तालाब की खुदाई कराई गई। ग्राम पंचायत अंडा ने क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में पूरे कार्य का सफल संचालन किया तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा। आज कृषि तालाब तैयार होने के बाद ममता चंद्राकर के खेत में वर्षा जल का संरक्षण संभव हो गया है। इससे पूरे वर्ष सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहने की संभावना बढ़ गई है। अब वे धान के साथ दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलों की खेती की योजना बना रही हैं। भविष्य में तालाब में मत्स्य पालन कर अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी मिलेगा। इसके साथ ही क्षेत्र में भूजल स्तर सुधारने और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

आयुक्त ने विभिन्न जोनों का किया निरीक्षण

जलभराव और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह ने निगम क्षेत्र के विभिन्न जोनों का निरीक्षण कर नागरिकों से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जोन-1 नेहरू नगर स्थित बाम्बे आवास के पास डूबान क्षेत्र, जोन-2 रामनगर स्थित नवीन पानी टंकी तथा जोन-3 अंतर्गत दुर्गापारा स्थित तालाब का बारीकी से अवलोकन किया। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जलभराव, पेयजल व्यवस्था और स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आयुक्त ने सबसे पहले जोन-1 नेहरू नगर क्षेत्र में बाम्बे आवास के पास स्थित डूबान क्षेत्र का निरीक्षण किया। बरसात के दौरान अधिक बारिश होने पर यहां

जलभराव की स्थिति निर्मित होने से नागरिकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए आयुक्त ने अधिकारियों से क्षेत्र की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए नालियों की नियमित सफाई कराई जाए। नालियों में कचरा, गाद एवं अन्य अवरोध जमा न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखने के साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए।

इसके पश्चात निगम आयुक्त ने जोन-2 रामनगर स्थित नवीन पानी टंकी का निरीक्षण किया। उन्होंने पानी टंकी की वर्तमान स्थिति एवं संचालन व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों से जानकारी ली। आयुक्त ने टंकी से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र के नागरिकों को नियमित एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

निरीक्षण के अगले चरण में आयुक्त ने जोन-3 अंतर्गत दुर्गापारा स्थित तालाब का भी जायजा लिया। उन्होंने तालाब एवं उसके आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को नियमित रूप से सफाई कराने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने कहा कि तालाब के आसपास गंदगी एवं कचरा जमा न होने दिया जाए तथा नागरिकों द्वारा तालाब के किनारे कचरा फेंकते पाए जाने पर तत्काल चालानी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता व्यवस्था की सतत निगरानी करने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, कुलदीप गुप्ता, कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल, अनिल सिंह, अरविंद शर्मा, सहायक अभियंता श्वेता वर्मा, नितेश मेश्राम, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, उप अभियंता पुरुषोत्तम सिन्हा, शंकर सुमन मरकाम, दीपक देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी जे.पी. तिवारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, बीरेन्द्र बंजारे एवं स्वच्छता निरीक्षक अंजनी सिंह, चुड़ामणी यादव सहित निगम के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में सीआईए पोर्टल लागू करने की पहल

रायपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय (एसजीजीवी), सरगुजा ने विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों (यूटीडी) एवं संघटक महाविद्यालयों में सतत आंतरिक मूल्यांकन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए समर्पित ष्ट्ठ पोर्टल लागू करने की पहल की है। इस संबंध में बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन एवं ऑफ्लाइन) में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष एवं संकाय सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कंप्यूटर विज्ञान विभाग के सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. रेशमलाल प्रधान के स्वागत उद्बोधन से हुई। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत सतत आंतरिक मूल्यांकन की महत्ता बताते हुए कहा कि सीआईए पोर्टल विद्यार्थियों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के लिए एक प्रभावी डिजिटल मंच साबित होगा, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी।

प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना ने बदली दिव्यांग परस कमार की जिंदगी

रायपुर। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत् परस कमार का पक्का घर बन जाने से उसके जीवन में कई बदलाव आया। अब बार -बार मरम्मत नहीं करना पड़ रहा है। बलैदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड अंतर्गत ग्राम बल्दाकछार के निवासी परस कमार विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय से संबंध रखते हैं। उनका जीवन संघर्ष, अभाव और कठिनाइयों से भरा रहा है। परस कमार पैर से दिव्यांग हैं, जिसके कारण रोजमर्रा के छोटे-छोटे कार्य भी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं थे। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया और उनकी माताजी भी अति वृद्ध हैं, जो उम्र और कमजोरी के कारण स्वयं सहारे की मोहताज हैं।आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वर्षों तक वे एक कच्चे और जर्जर मकान में रहने को मजबूर थे। बरसात के दिनों में छत से टपकता पानी, ठंडी रातों में टूटती दीवारों से आती हवा, और गर्मी के मौसम में तपता हुआ घर यही उनकी जिंदगी की सच्चाई थी।

स्वतंत्र एटीएमए जिला बनने की दिशा में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की बड़ी पहल

रायपुर। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले को स्वतंत्र एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी (एटीएमए) जिला बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर एवं आत्मा योजना के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा संचालित केंद्र प्रवर्तित एक्सटेंशन रिफॉर्म (एटीएमए) योजना के अंतर्गत जिले की स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्लान (एसआरईपी) तैयार करने के लिए चयनित तीन ग्रामों में पार्टिसिपेटरी रूरल एप्रेजल (पीआरए) सर्वेक्षण सफ्लतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। सर्वेक्षण विकासखंड मोहला के ग्राम रेंगाकठेरा, विकासखंड मानपुर के ग्राम बसेली तथा विकासखंड अंबागढ़ चौकी के ग्राम बागनारा में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। इस दौरान किसानों, महिला समूहों एवं ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी एकत्रित की गई।

कृषि, पशुपालन और उद्यम से जुड़ी महिलाएं, अब स्थानीय बीजों और अनाजों से बना रहीं राखियां

स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को मिला आजीविका का नया अवसर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कृषि, पशुपालन और विभिन्न उद्यम गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहीं रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड की महिलाएं अब स्थानीय बीजों और अनाजों से आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़ी स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने रक्षाबंधन पर्व को आजीविका से जोड़ते हुए बीज राखियों का निर्माण शुरू किया है। स्थानीय संसाधनों से तैयार हो रही ये राखियां महिलाओं को अतिरिक्त आय का अवसर देने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही हैं।

गौरतलब है कि स्व-सहायता समूहों की महिलाएं विभिन्न प्रकार के बीजों और अनाजों से आकर्षक बीज राखियां तैयार कर रही हैं। इनमें बरबट्टी, मक्का, कुम्हड़ा, लौकी, करेला, सेमी, ग्वारफली, भिंडी, उड़द, मसूर, मूंगफली, धान और चावल जैसे स्थानीय बीजों का उपयोग किया जा रहा है। फेवीकोल, रंग, स्टीकर और धागे की सहायता से तैयार की जा रही ये राखियां आकर्षक होने के साथ पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। इन बीज राखियों की खासियत यह है कि रक्षाबंधन के बाद इन्हें मिट्टी में दबाने पर इनमें मौजूद बीज अंकुरित होकर पौधे का रूप ले सकते हैं। इस तरह ये राखियां भाई-बहन के प्रेम के प्रतीक के साथ प्रकृति संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का माध्यम भी बनेंगी। धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत कोयलार की जय ठाकुरदेव स्व-सहायता समूह की सदस्य एवं कृषि सखी श्रीमती गणपति राठिया ने बताया कि समूह की महिलाओं ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विभिन्न बीजों से राखियां तैयार की हैं।

उन्होंने बताया कि कृषि और अन्य आजीविका गतिविधियों के साथ अब समूह की महिलाएं त्योहारी आवश्यकताओं से जुड़े उत्पादों का निर्माण भी कर रही हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय का अवसर मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीज राखी निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद जिले के विभिन्न विकासखंडों में स्व-सहायता समूहों द्वारा बीज राखियों का निर्माण किया जा रहा है। 20 जुलाई को जनपद पंचायत पुसौर, रायगढ़, धरमजयगढ़, खरसिया, तमनार एवं घरघोड़ा से प्राप्त स्व-सहायता समूहों की दीदियों द्वारा निर्मित बीज राखियों का चयन समिति द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

धरमजयगढ़ में तैयार राखियों का पहला बैच जिले में भेजा जा चुका है और जल्द ही इनकी बिक्री प्रारंभ होगी। बिहान से जुड़ी महिलाएं कृषि, पशुपालन, लघु उद्यम सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। बीज राखियों का निर्माण उनके लिए आजीविका के एक नए साधन के रूप में सामने आया है। स्थानीय संसाधनों से तैयार ये राखियां इस रक्षाबंधन रिश्तों की मिठास के साथ पर्यावरण संरक्षण और महिला आत्मनिर्भरता का संदेश भी देंगी।

विष्णुभोग चावल बना जीपीएम जिले का गौरव

महिला स्व-सहायता समूहों को मिला स्थायी रोजगार, सुगंधित विष्णुभोग चावल देशभर में बना छत्तीसगढ़ की पहचान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास लगातार सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। भारत सरकार की एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले का पारंपरिक सुगंधित विष्णुभोग चावल आज प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। प्राकृतिक खेती, उत्कृष्ट गुणवत्ता और आकर्षक ब्रांडिंग के कारण विष्णुभोग चावल अब जीपीएम जिले की नई पहचान बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार स्थानीय कृषि उत्पादों को मूल्य संवर्धन, आधुनिक विपणन और ब्रांडिंग से जोड़कर किसानों को बेहतर आर्थिक अवसर उपलब्ध करा रही है। इसी सोच का परिणाम है कि जीपीएम जिले का पारंपरिक विष्णुभोग चावल आज किसानों की समृद्धि और महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बन चुका है।

जिले के पेंड्रा क्षेत्र में लगभग 1,500 किसान करीब 600 एकड़ भूमि पर विष्णुभोग धान की खेती कर रहे हैं।

अपनी मनमोहक सुगंध, बेहतरीन स्वाद और पौष्टिक गुणों के कारण यह धान उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनती जा रही है। किसानों द्वारा प्राकृतिक और पारंपरिक पद्धति से की जा रही खेती ने इसकी गुणवत्ता को और अधिक विशिष्ट बनाया है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ-साथ जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिल रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को भी उत्पादन और विपणन की मुख्यधारा से जोड़ रही है। इसी क्रम में मलनिया महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, पेंड्रा किसानों से विष्णुभोग धान की खरीदी कर उसका प्रसंस्करण मिनी राइस मिल में कर रही है। आधुनिक पैकेजिंग और आकर्षक ब्रांडिंग के माध्यम से तैयार चावल को बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस पहल से समूह की 15 महिलाओं को स्थायी रोजगार प्राप्त हुआ है। महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और लखपति दीदी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब तक समूह द्वारा लगभग 2 टन विष्णुभोग चावल की सफ्ल बिक्री की जा चुकी है, जिससे करीब एक लाख रुपये का लाभ अर्जित हुआ है। लगातार बढ़ती मांग ने महिलाओं के आत्मविश्वास और उत्साह को नई ऊर्जा दी है।

विष्णुभोग चावल की बढ़ती लोकप्रियता ने जीपीएम जिले के किसानों के लिए नए बाजारों के द्वार खोल दिए हैं। जिले से बाहर प्रदेश के अन्य जिलों तथा विभिन्न राज्यों से भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। यह सफ्लता इस बात का प्रमाण है कि यदि स्थानीय उत्पादों को उचित पहचान, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और विपणन का अवसर मिले, तो वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले की विशिष्टता को देश-दुनिया तक पहुंचाना है, ताकि स्थानीय उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, किसानों की आय में निरंतर वृद्धि हो और महिलाओं को स्वावलंबन के नए अवसर मिलें। एक जिला-एक उत्पाद योजना इसी दूरदर्शी सोच को साकार कर रही है।

विष्णुभोग चावल आज केवल एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि जीपीएम जिले की समृद्ध कृषि परंपरा, किसानों की मेहनत, महिला शक्ति के आत्मविश्वास और छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक एवं कृषि विरासत का प्रतीक बन चुका है। आने वाले समय में इसके उत्पादन, ब्रांडिंग और विपणन को और अधिक विस्तार मिलने से यह उत्पाद राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

'कांकेयर' ब्रांड बना ग्रामीण महिलाओं की पहचान

शुद्ध जैविक उत्पादों की लगातार बढ़ रही मांग

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार 'कांकेयर' ब्रांड तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। यह ब्रांड कांकेर की हजारों महिलाओं की मेहनत, आत्मनिर्भरता और गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक उत्पादों का प्रतीक बन चुका है।

'कांकेयर' ब्रांड के तहत सरसों तेल, अरहर दाल, छिंद गुड़, शहद, रागी, कोदो, मक्का, आम का अचार सहित विभिन्न जैविक एवं प्राकृतिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। दण्डकारण्य क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों में उगाए गए ये उत्पाद पूरी तरह शुद्ध, प्राकृतिक और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। ये उत्पाद स्वसहायता समूहों द्वारा पारंपरिक एवं जैविक पद्धति से तैयार किए जाते हैं, जिनमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है।

एफ्एसएसएआई से पंजीकृत होने के कारण उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है।

वर्तमान में 'कांकेयर' उत्पादों का सी-मार्ट और कांकेश्वरी एफ्पीसी के माध्यम से स्थानीय बाजारों में वितरण और बिक्री सुनिश्चित की जा रही है। जिला पंचायत परिसर में स्थापित पैकेजिंग इकाई से इनकी थोक खरीदी की जा सकती है। वेबसाइट के माध्यम से इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर घर बैठे शुद्ध एवं प्राकृतिक उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। कांकेर जिला पंचायत के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 'कांकेयर' ब्रांड के 92 किलोग्राम अरहर दाल , 5.5 किलोग्राम शहद, 5 किलोग्राम छिंद गुड़, 9 किलोग्राम रागी आटा तथा 6 किलोग्राम मक्का आटा की बिक्री हो चुकी है।

'कांकेयर' ब्रांड आज केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि कांकेर जिले की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता और गुणवत्तापूर्ण जैविक उत्पादन की नई पहचान बनकर उभर रहा है।

पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिस जवानों का जाना हाल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर में आज एक रैली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और रैली को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल द्वारा बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा अचानक पत्थर एवं बोतलें फेंके जाने से अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई, जिसमें ड्यूटी पर तैनात पुलिस के 16 जवान घायल हो गए। घायलों में एक महिला आरक्षक शामिल थी, दो पुलिस जवानों को गंभीर चोटें आई हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही रायपुर के पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला में अस्पताल पहुंच भर्ती पुलिस जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से घायल जवानों के स्वास्थ्य एवं उपचार की विस्तृत जानकारी ली तथा सभी घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। घायल जवान कलेश्वर वर्मा ने बताया कि बैरिकेटिंग के दौरान भीड़ के बीच फंस जाने से उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई, जिसके बाद

उन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया। वहीं, प्रशिक्षु उप निरीक्षक (पीएसआई) देवराज सिंह के सिर पर बोतल लगने से गंभीर चोट आई है, जिनका उपचार चिकित्सकों की निगरानी में जारी है।

अन्य घायल आरक्षकों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान पुलिस उपायुक्त (मध्य) तारकेश्वर पटेल, एसीपी नीलेश द्विवेदी, टीआई राजेश मरई सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

कभी नक्सलवाद का गढ़ रहा बीजापुर का पीड़िया : अब विकास की राह पर, 21 साल बाद फिर खुला स्कूल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बीजापुर जिले की गंगालूर तहसील का ग्राम पंचायत पीड़ियां अब भय और नक्सली गतिविधियों के साये से बाहर निकलकर बदलाव की एक नई कहानी लिख रहा है। कभी नक्सली प्रभाव के लिए पहचाना जाने वाला यह सुदूर गांव अब शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं से जुड़कर विकास की मुख्यधारा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। नक्सली हिंसा के कारण बीते 21 वर्षों से बंद पड़ा गांव का स्कूल अब दोबारा शुरू हो गया है।

क्षेत्र में आए सकारात्मक बदलाव और निर्मित कच्चे मार्गों की बदौलत अब प्रशासन की पहुंच पीड़ियां गांव तक आसान हुई है। इसी कड़ी में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के

लिए गांव में पहली बार विशेष आधार नामांकन एवं अद्यतन शिविर का आयोजन किया गया।

नेटवर्कविहीन और दूरस्थ क्षेत्र होने के बावजूद, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचे।

तकनीकी चुनौतियों के बीच शिविर में 80 ग्रामीणों का आधार पंजीयन और अद्यतन कार्य सफ्लतापूर्वक पूरा किया गया। आधार कार्ड बनने से अब ग्रामीणों के लिए राशन, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा।

पीड़ियां में बदलाव की सबसे सुंदर और बड़ी तस्वीर शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। नक्सली हिंसा के कारण बीते 21 वर्षों से बंद पड़ा गांव का स्कूल अब दोबारा शुरू हो गया है। वर्तमान में 84 बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। लंबे समय बाद स्कूल की घंटी बजने से बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और गांव की तरक्की को नई दिशा मिली है।

पहचान से अधिकार और अधिकार से विकास

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पहले नक्सली गतिविधियों के कारण सामान्य जीवन व्यतीत करना और सरकारी सेवाओं तक पहुँचना बेहद कठिन था। लेकिन अब गांव में शांति का माहौल है और विकास की नई किरण दिखाई दे रही है। पीड़ियां में आयोजित यह शिविर केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शासन की सेवाओं के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने और विश्वास बहाली का एक मजबूत प्रतीक बन चुका है।

तमनार के युवाओं के कौशल विकास को नई दिशा, निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ मिलेगी टूल-किट, ड्रेस और प्लेसमेंट में सहायता

आईटीआई भवन में औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की मंशानुरूप युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर तमनार क्षेत्र के युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और जिंदल पावर तमनार के बीच विशेष पहल की गई है।

इसी पहल के तहत बुधवार को तमनार स्थित शासकीय आईटीआई भवन में जिंदल फाउंडेशन द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में तकनीकी कौशल प्रदान किया जाएगा,

जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।

जिंदल पावर के एवीपी (सीएसआर) ऋषिकेश राय शर्मा ने कहा कि शासन की मंशा, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और जिंदल पावर के सहयोग से यह पहल धरातल पर साकार हो रही है। उन्होंने बताया कि युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए ओपीजेसी पूंजीपथरा के साथ समन्वय किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद सभी प्रशिक्षार्थियों को आवश्यक टूल-किट और ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही योग्य युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्लेसमेंट में भी सहायता प्रदान की जाएगी।

जिला खनिज अधिकारी श्री आर.के. सोनी ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को कुशल बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल प्रमाण-पत्र देना नहीं, बल्कि युवाओं को वास्तविक कौशल प्रदान कर रोजगार योग्य बनाना है। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों से नियमित रूप से प्रशिक्षण में उपस्थित रहने और पूरी लगन के साथ सीखने का आह्वान किया। कार्यक्रम को शासकीय आईटीआई तमनार के प्राचार्य पुष्कर कुमार कंवर एवं ओपीजेयूसी के डायरेक्टर जितेंद्र कुमार ने भी संबोधित किया।

जिंदल पावर के एजीएम (सीएसआर) राजेश रावत ने बताया कि प्रशिक्षण में शामिल युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि प्रशिक्षार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही आईटीआई के अधोसंरचना विकास के लिए भी आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं।

इस प्रशिक्षण केंद्र में प्रथम चरण में युवाओं को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा फिटर और वेल्डर ट्रेड के लिए भी सर्वे किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण का लाभ मिल सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य तमनार क्षेत्र के खदान एवं औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित गांवों के युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इससे स्थानीय युवा उद्योगों की जरूरत के अनुरूप दक्षता हासिल कर सकेंगे और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

गंजेपन से मुक्ति
मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में
JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बेंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131
अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, कैम्प 2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

हमेशा हिफाजत करूंगा, वह परिवार जैसी हैं

शहनाज गिल संग रिश्ते की चर्चाओं पर बोले राघव जुयाल

राघव जुयाल और शहनाज गिल के अफेयर को लेकर काफी वक्त से अटकलें लगाई जा रही हैं। बीते दिनों राघव की बर्थडे पार्टी से एक वीडियो सामने आया, जिसने इन चर्चाओं को और हवा दी। राघव ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। जानिए क्या कहा?

राघव जुयाल और शहनाज गिल का नाम पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है। हाल ही में एक बर्थडे पार्टी से बाहर निकलते वक्त दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में भीड़ के बीच राघव, शहनाज को सुरक्षित बाहर निकालते नजर आए थे। इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया। इसी बीच शहनाज गिल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में निजी जिंदगी से जुड़े सवाल को टालते हुए राघव जुयाल को अपना 'बहुत अच्छा दोस्त' बताया था। साथ ही उन्होंने उनकी पहली लीड फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' का समर्थन करते हुए लोगों से फिल्म देखने की अपील की थी। राघव जुयाल ने भी उस पर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

'पर्सनल लाइफ की चर्चा तो होगी'

जब राघव जुयाल से उनकी पर्सनल लाइफ और शहनाज गिल के साथ जुड़ रहे नाम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'देखिए, पर्सनल लाइफ की चर्चा तो होगी। हम शोबिज में हैं। हम लोग फेमस हैं। आगे भी ऐसी बातें होंगी।'

'शहनाज मेरे लिए परिवार जैसी हैं'

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन, हम सब दोस्त हैं। शहनाज भी मेरी दोस्त है। मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूं। वह मेरे लिए परिवार जैसी है। मैं अपने दोस्तों और परिवार की हमेशा हिफाजत करता हूं और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। यह तो तय है।'

2023 में भी उड़ी थीं डेटिंग की अफवाहें

राघव जुयाल और शहनाज गिल ने सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में साथ काम किया था। फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने दोनों की केमिस्ट्री को लेकर मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की थी। इसके बाद दोनों के डेटिंग की खबरों ने जोर पकड़ लिया था। हालांकि, बाद में राघव जुयाल ने इन चर्चाओं पर सफाई देते हुए कहा था कि सलमान खान ने सिर्फ मजाक किया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनके और शहनाज के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था।

रेखा के साथ उत्सव फिल्म की शूटिंग पर शेखर सुमन का खुलासा

बोले- 'उन्होंने कभी नहीं कहा, मुझे यहां-वहां मत छुओ'

शेखर सुमन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने फिल्मी डेब्यू 'उत्सव' में रेखा के साथ काम करने का अनुभव साझा करते हुए बताया कि रेखा ने सेट पर उन्हें सहज महसूस कराया और उनकी प्रोफेशनलिज्म की जमकर तारीफ की। इन दिनों शेखर सुमन अपने टॉक शो 'शेखर टुनाइट' को लेकर सुर्खियों में हैं। अपने इस शो में वो देश में फैले मुद्दों, राजननीति और फिल्मों पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। उनके ये सटायर सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं। हाल ही में शेखर सुमन ने अपनी पहली फिल्म 'उत्सव' और दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ काम करने के अपने अनुभव पर बात करते हुए उनके साथ किए बोल्ड सीन्स के बारे में भी खुलकर बात की और बताया कि कैसे रेखा ने उन्हें सेट पर बहुत कम्फर्टेबल फील कराया।

रेखा के साथ शेखर सुमन की डेब्यू फिल्म उत्सव

साल 1984 में गिरीश कर्नाड की फिल्म उत्सव रिलीज हुई थी, जो एक रोमांटिक-इरोटिक फिल्म थी और शेखर सुमन ने इसी फिल्म में एक दमदार किरदार निभाकर अपने फिल्मी डेब्यू किया था। बता दें कि इस फिल्म को शशि कपूर ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें रेखा ने वसंतसेना नाम की एक गणिका का रोल प्ले किया था, जो उज्जैन में चारुदत्त (शेखर) नाम के एक गरीब आदमी से मिलती है।

रेखा के साथ काम करने पर शेखर सुमन

रेखा के साथ काम करने पर शेखर सुमन ने कहा, रेखा जी ने शुरू से ही मुझे बहुत सहज महसूस कराया। कई बड़े स्टार्स अपने साथ बड़ी टीम लेकर चलते हैं और ऐसा माहौल बना देते हैं कि बाकी लोग उनसे बात करने में भी हिचकें। लेकिन रेखा जी उनसे बिल्कुल अलग थीं। उनमें स्टार होने का कोई घमंड नहीं था। वो मेरे पास आकर बैठती थीं, बातें करती थीं और मेरा हौसला बढ़ाती थीं। इसी वजह से कैमरे के सामने जाने से पहले ही मेरा डर खत्म हो गया था और मैं पूरी तरह सहज महसूस कर रहा था।

डायरेक्टर गिरीश कर्नाड के बारे में भी की खुलकर बात

शेखर ने डायरेक्टर गिरीश कर्नाड को निफल्म का श्रेय देते हुए कहा कहा, उन्होंने मुझसे कहा, 'देखो, तुम बस एक किरदार निभा रहे हो। उसे रेखा मत समझो, बल्कि वसंतसेना समझो, जो एक दूसरा किरदार है। उन्होंने साथ में इंटीमेट सीन शूट करते समय रेखा के प्रोफेशनलिज्म की भी तारीफ की। शेखर ने आगे कहा, एक बड़ी स्टार होने के बावजूद, उन्होंने कभी नहीं कहा कि 'मुझे यहां मत छुओ' या 'मैं एक और रीटेक नहीं देना चाहती'। वो बहुत ही नॉर्मल थीं।

महिला प्रधान फिल्मों पर बोले शेखर सुमन

शेखर सुमन ने अपने करियर की शुरुआत में कई ऐसी फिल्मों में काम किया, जिनमें कहानी महिला किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती थी। इनमें 'उत्सव', 'मानव हत्या' और 'रहगुजर' जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि, उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी फिल्में कोई खास बात सोचकर नहीं चुनी थीं। शेखर ने कहा, मुझे जो भी अच्छा काम मिला, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। 'उत्सव' मेरे लिए शानदार अनुभव था। रेखा जैसी बड़ी स्टार के साथ हीरो के तौर पर चुना जाना मेरे लिए बड़ी बात थी। उनका रोल मुझसे बड़ा था, लेकिन फिल्म में मेरा किरदार भी काफी अहम था और लोगों ने मेरे काम को नोटिस किया।

'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग में धमाका, रिलीज से पहले ही करोड़ों रुपये, 7 लाख टिकट बिके

काफी मशक्कतों के बाद विजय की फिल्म जन नायकन आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। एडवांस बुकिंग में ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है।

एडवांस बुकिंग में कमाए इतने करोड़

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने भारत में रिलीज से एक दिन पहले ही 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली है, जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं। अगर ब्लॉक सीट्स को हटाया जाए तो भी फिल्म करीब 14 करोड़ रुपये की टिकट सेल कर चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा तमिल वर्जन का है।

तमिलनाडु फिल्म का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जहां से करीब 7.90 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, जहां से 6.03 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, खासकर बेंगलुरु में जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है। केरल से भी 1.91 करोड़ रुपये की अच्छी कमाई हुई है।

बेंगलुरु में हुई सबसे ज्यादा बुकिंग

शहरों की बात करें तो बेंगलुरु सबसे आगे है, जहां से 5.99 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है। इसके बाद चेन्नई (1.86 करोड़), कोयंबटूर (90 लाख) और हैदराबाद, मदुरै, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों से भी अच्छे आंकड़े सामने आए हैं।

भाषा के हिसाब से तमिल वर्जन पूरी तरह हावी है, जहां से 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हुई है। तेलुगु वर्जन का कलेक्शन थोड़ा कम है, जबकि हिंदी वर्जन को अभी तक सीमित रिस्पॉन्स मिला है।

फैंस में बढ़ी एक्साइटमेंट

हालांकि, 'जन नायकन' अभी विजय की पिछली फिल्मों 'लियो' और 'GOAT' से पीछे चल रही है, लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि रिलीज के करीब आते-आते बुकिंग में और तेजी आ सकती है।

इस फिल्म को लेकर फैंस में खास एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि यह विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है। 33 साल के करियर के बाद वह फिल्मों को अलविदा कह रहे हैं और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं।

फिल्म के स्टारकास्ट और रिलीज डेट

एच विनोथ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियामणि, नारायण और नासर जैसे कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म पहले 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से देरी के बाद अब 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'बाथरूम के सीन में हुई असहज', थप्पड़कांड के सालों बाद सान्वी तलवार का बड़ा दावा,

बोलीं- करण कुंद्रा की मुझमें दिलचस्पी थी

टीवी इंडस्ट्री का चर्चित 'ये कहां आ गए हम' थप्पड़ विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। करीब एक दशक बाद अभिनेत्री सान्वी तलवार ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई अहम दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि करण कुंद्रा में उनकी नहीं, बल्कि करण की उनमें दिलचस्पी थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सेट पर असहज महसूस होने के बाद उन्होंने करण की उस समय की गर्लफ्रेंड अनुषा डांडेकर से भी शिकायत की थी।

'करण मुझमें दिलचस्पी रखते थे'

'इंडिया फोरम' के साथ एक इंटरव्यू में सान्वी तलवार ने कहा कि वर्षों से लोगों के बीच ये धारणा बनी रही कि उन्हें करण कुंद्रा पसंद थे, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। सान्वी के मुताबिक, करण उनकी तरफ आकर्षित थे और यह भावना उनकी ओर से नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस गलतफहमी ने लंबे समय तक विवाद को हवा दी। उनका कहना है कि वह स्थिति उनके लिए सहज नहीं थी, इसलिए उन्होंने चुप रहने के बजाय इस बारे में बात करना बेहतर समझा।

इसी वजह से उन्होंने अनुषा डांडेकर से संपर्क कर अपनी परेशानी साझा की। अनुषा डांडेकर से की थी शिकायत। गौरतलब है कि साल 2015 में 'ये कहां आ गए हम' के सेट पर करण कुंद्रा और सान्वी तलवार के बीच थप्पड़ मारने की घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। उस समय दोनों कलाकारों के बीच हुए विवाद पर कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आई थीं। अब सान्वी के नए खुलासों के बाद ये मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर करण कुंद्रा की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है।

'लोगों ने मुझे बस सिगरेट और साड़ी में देखा'

इंडस्ट्री में एक ही तरह के रोल मिलने पर छलका माही गिल का दर्द

बॉलीवुड अभिनेत्री माही गिल अमेजन प्राइम की वेब सीपीज रक्तांचल के सीजन 3 को लेकर इन दिनों चर्चाओं में हैं। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी सफर को याद करते हुए बताया कि एक समय ऐसा था जब इंडस्ट्री में उन्हें सिर्फ एक तय छवि के साथ देखा जाता था।

हर नई फिल्म में लगभग एक जैसे किरदार मिलने लगे थे, जिससे वो खुद भी ऊब चुकी थीं। अभिनेत्री का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने न सिर्फ उनके अभिनय को नई दिशा दी, बल्कि उन्हें अपनी स्थापित छवि से बाहर निकलकर अलग तरह के किरदार निभाने का अवसर भी दिया।

'रक्तांचल 3' के प्रमोशन के दौरान छलका दर्द

हाल ही में अपनी वेब सीरीज 'रक्तांचल 3' के प्रमोशन के दौरान 'इंडिया टुडे' के साथ बातचीत करते हुए माही गिल ने खुलकर बताया कि कई सालों तक उन्हें ग्लैमरस महिला के रोल ही ऑफर किए जाते रहे। फिल्म निर्माताओं की सोच भी उनके लिए लगभग तय हो चुकी थी। उन्हें अक्सर ऐसी महिला के रूप में पेश किया जाता था जो साड़ी पहनती हो, सिगरेट पीती हो और बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आती हो। लगातार एक जैसी भूमिकाएं निभाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि अब कुछ नया करने का समय आ गया है।

'रक्तांचल 3' में सरस्वती देवी का किरदार

अभिनेत्री ने कहा कि वो उन किरदारों से नाराज नहीं थीं और भविष्य में भी ऐसे रोल करना चाहेंगी, लेकिन लगातार एक ही तरह की भूमिकाएं निभाने से कलाकार के तौर पर उनकी पहचान सीमित होती जा रही थी। इसी वजह से जब 'रक्तांचल 3' में सरस्वती देवी का किरदार उनके पास आया तो उन्होंने इसे अपने करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक माना।

माही गिल के मुताबिक इस किरदार के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी भाषा और स्थानीय बोली थी। उन्होंने बताया कि शरीर की अभिव्यक्ति पर काम करना आसान था, लेकिन संवादों में इस्तेमाल होने वाली बोली को सही ढंग से बोलने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। यही वजह है कि यह किरदार उनके लिए सीखने और खुद को साबित करने का नया मौका बन गया।

माही गिल ने लिया था चार साल का लंबा ब्रेक

माही गिल ने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपने करियर के बीच लगभग चार साल का लंबा ब्रेक लिया था। इस दौरान कई अच्छे प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए। हालांकि उन्हें इसका अफसोस नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि अगर वह उस समय लगातार काम कर रही होतीं तो कई सफल वेब सीरीज और फिल्मों का हिस्सा बन सकती थीं।

जिला अस्पताल में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर, विशेषज्ञों ने दी जांच और उपचार संबंधी सलाह

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायगढ़ जिले में कैंसर की समय पर पहचान और उपचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किरोड़ीमल शासकीय जिला चिकित्सालय में बुधवार को निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्पताल और बालको मेडिकल सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर आवश्यक सलाह दी। शिविर का शुभारंभ महापौर जीवर्धन चौहान ने किया। शिविर में महिलाओं के लिए स्तन कैंसर

की जांच हेतु मैमोग्राफी मशीन एवं थर्मल स्केनर तथा गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही मुंह एवं मुखगुहा के कैंसर की जांच, आवश्यक नमूना संग्रहण तथा बीपी, ब्लड सुगर एवं बीएमआई की निःशुल्क जांच भी की गई।

शिविर के दौरान 10 स्तन कैंसर, 10 मुंह एवं मुखगुहा कैंसर, 2 प्रोस्टेट कैंसर, 2 रक्त कैंसर तथा 3 गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के मरीजों की जांच कर विशेषज्ञों ने उपचार संबंधी सलाह दी। इसके अलावा 40 महिलाओं की स्वाईकल कैंसर की स्क्रीनिंग तथा 10 महिलाओं की मैमोग्राफी जांच भी की गई। महापौर श्री जीवर्धन चौहान ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की समय पर पहचान जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे शिविरों से जिले के लोगों को स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, जो सराहनीय पहल है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत ने कहा कि कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में पहचान होने पर उसका सफल उपचार संभव है। ऐसे शिविर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ जोखिम वाले मरीजों की समय पर जांच सुनिश्चित करते हैं। सिविल सर्जन डॉ. दिनेश कुमार पटेल ने बताया कि यदि स्तन में गांठ, मुंह में लंबे समय तक रहने वाला घाव, निगलने में कठिनाई, आवाज में बदलाव, लगातार खांसी, बिना कारण वजन घटना या अन्य संदिग्ध लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सक से जांच करानी चाहिए। शिविर में बालको मेडिकल सेंटर से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. राजेंद्र प्रसाद पटेल एवं मेडिकल ऑफिसर डॉ. हेमलता उपस्थित रहे। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री रंजना पैंकरा, गैर संचारी रोग कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. जाविद मारिकर, डॉ. सुमित कुमार, डॉ. शैलेंद्र मंडल, सीमा बरेठ सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

खास-खबर

बस्तर में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की मजबूत कड़ी बने 'नल जल मित्र'

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अभिनव पहल 'नल जल मित्र' योजना प्रभावी परिणाम दे रही है। बस्तर जिले में प्रशिक्षण प्राप्त स्थानीय युवा अब ग्राम पंचायतों में नल-जल योजनाओं एवं हैंडपंपों के संचालन, संधारण और मरम्मत की जिम्मेदारी निभाते हुए ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की मजबूत रीढ़ बन रहे हैं। इससे एक ओर ग्रामीणों को पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान मिल रहा है, वहीं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल जल मित्रों को लाइवलीहुड कॉलेज जगदलपुर में आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे तकनीकी रूप से दक्ष होकर ग्राम पंचायतों में जल प्रदाय योजनाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित कर सकें।

जशपुर जिले में 2 लाख 72 हजार साजा-अर्जुन पौधों का पौधरोपण शुरू

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की सोच को आगे बढ़ाते हुए जशपुर जिले में बड़े पैमाने पर साजा और अर्जुन के पौधों का पौधरोपण कार्य शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाने के साथ-साथ स्व-सहायता समूह की महिलाओं एवं ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है। विकासखंड फरसाबहार, दुलदुला, पत्थलगांव और कुनकुरी में वर्ष 2026-27 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत पौधरोपण अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 19 स्थलों पर 66.5 हेक्टेयर भूमि में साजा और अर्जुन के पौधों का रोपण स्वीकृत किया है। प्रत्येक स्थल पर लगभग 14,350 पौधों के हिसाब से कुल 2 लाख 72 हजार 650 पौधों की नर्सरी तैयार कर पौधरोपण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि करना है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की कॉलोनियों में लाखों रुपये का मेंटेनेंस शुल्क बकाया

श्रीकंचनपथ न्यूज

डूमरतराई एवं बोरियाकला कॉलोनियों के बकायादार हितग्राहियों से शीघ्र भुगतान की अपील

रायपुर। रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की बहुमंजिली भवन हिमालयन हाइट्स, डूमरतराई एवं बोरियाकला कॉलोनियों में हितग्राहियों द्वारा लैंड मेंटेनेंस चार्ज (एल.एम.सी.), कॉमन मेंटेनेंस चार्ज (सी.एम.सी.) तथा जल प्रभार का नियमित भुगतान नहीं किए जाने के कारण कॉलोनियों के रखरखाव एवं नागरिक सुविधाओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मंडल द्वारा कॉलोनियों में सड़कों, नालियों, उद्यानों, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य रखरखाव कार्यों पर नियमित व्यय किया जाता है। इन कार्यों के लिए आवश्यक राशि एल.एम.सी., सी.एम.सी. एवं जल प्रभार के माध्यम से प्राप्त होती है।

निर्धारित शुल्क समय पर जमा नहीं होने से इन आवश्यक सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से लिफ्टों के नियमित संचालन एवं रखरखाव, विद्युत देयकों (बिजली बिल) के समय पर भुगतान तथा कॉलोनियों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों के सुचारु संचालन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो

रही हैं। इससे कॉलोनियों में उपलब्ध कराई जाने वाली नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। हिमालयन हाइट्स, डूमरतराई कॉलोनी में लगभग 800 आबंटित भवनों के विरुद्ध 197 हितग्राहियों से लगभग रु.185.35 लाख की मेंटेनेंस शुल्क राशि बकाया है। इनमें से रु.1.50 लाख से अधिक के 13 रहवासी, रु.1.00 लाख से रु.1.50 लाख के 50 रहवासी, रु.50 हजार से रु.1.00 लाख के 130 रहवासी तथा रु.50 हजार तक के 4 रहवासी की बकाया राशि लंबित है।

इसी प्रकार बोरियाकला कॉलोनी में लगभग 4,155 आबंटित भवनों के विरुद्ध 1716 हितग्राहियों से लगभग रु.345.20 लाख की मेंटेनेंस शुल्क राशि बकाया है। इनमें से रु.1.50 लाख से अधिक के 1 रहवासी, रु.1.00 लाख से रु.1.50 लाख के 5 रहवासी, रु.50 हजार से रु.1.00 लाख के 216 रहवासी तथा रु.50 हजार तक के 1494 रहवासी की बकाया राशि लंबित है।

मंडल के अधिकारियों के अनुसार मेंटेनेंस शुल्क की बकाया राशि लगातार बढ़ने से कॉलोनियों में आवश्यक रखरखाव कार्य समय पर कराना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव कॉलोनियों की समग्र व्यवस्था तथा रहवासियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सामुदायिक सुविधाओं पर पड़ रहा है।

बकाया राशि की वसूली हेतु प्रक्षेत्र रायपुर के संबंधित संभाग कार्यालय द्वारा सभी बकायादार हितग्राहियों को नोटिस जारी कर बकाया मेंटेनेंस शुल्क, एल.एम.सी., सी.एम.सी. एवं जल प्रभार की राशि शीघ्र जमा करने हेतु अनुरोध किया गया है। नोटिस में हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे समय पर बकाया राशि का भुगतान करें, जिससे कॉलोनियों के रखरखाव, लिफ्ट संचालन, साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ मंडल द्वारा निरंतर एवं सुचारु रूप से उपलब्ध कराई जा सकें।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र रायपुर के अपर आयुक्त एस.के. भगत ने सभी बकायादार हितग्राहियों से अपील की है कि वे एल.एम.सी., सी.एम.सी. एवं जल प्रभार की बकाया राशि शीघ्र जमा कर मंडल को कॉलोनियों के सुचारु रखरखाव, लिफ्ट संचालन, स्वच्छता व्यवस्था तथा बेहतर नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समयावधि में बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो मंडल के नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में बिहान दीदियों की बीज राखी बिखेरेगी हरियाली

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। भाई-बहन के अटूट प्रेम को जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित विभिन्न जिलों में 'बीज राखी' बनाने का अनूठा अभियान चलाया जा रहा है। त्योहार के बाद मिट्टी में मिलने पर इन राखियों में जड़े देसी बीज अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं। इन इको-फ्रेंडली राखियों में धान, सब्जियों और फूलों जैसे देसी बीज होते हैं। इन्हें फेंकने के बजाय अगर मिट्टी में डाल दिया जाए, तो ये हरियाली बिखेरते हैं। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व केवल रिश्तों की मिठास ही नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण का एक नया अध्याय भी लिखेगा। कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ के निर्देशन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की स्व-सहायता समूह की महिलाएं बड़े पैमाने पर पर्यावरण-अनुकूल राखियों के निर्माण में जुटी हैं। इस वर्ष बीज राखी थीम पर कुल 12 हजार 300 राखियां तैयार की जा रही हैं, जो भाई-बहन के पवित्र प्रेम के साथ-साथ समाज को हरियाली और पर्यावरण संवर्धन का सुंदर संदेश देंगी।

इन राखियों का मुख्य आकर्षण इनके केंद्र (मध्य) में रखे गए बीज हैं। रक्षाबंधन पर्व के उपरांत इन राखियों को मिट्टी या गमलों में रोपित किया जा सकेगा, जिससे नए पौधे अंकुरित होंगे। महिलाओं का यह अभिनव प्रयास समाज में पर्यावरण-जागरूकता फैलाने के साथ-साथ प्रकृति को संवारने का कार्य भी करेगा।

सेवा सेतु केंद्र से अब नव दंपत्तियों को विवाह प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान

श्रीकंचनपथ न्यूज

कवर्धा। विवाह के बाद आवश्यक शासकीय दस्तावेजों में विवाह प्रमाण पत्र का विशेष महत्व होता है। अब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से नव दंपत्तियों के लिए विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल और सुगम हो गई है। सेवा सेतु केंद्र में आवेदन करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा प्रक्रिया पूरी कर निर्धारित समय में विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

कबीरधाम जिले के ग्राम राम्हेपुर निवासी फलित पुरेना और उनकी पत्नी प्रियंका पुरेना ने भी इस सुविधा का लाभ उठाया। लगभग दो माह पूर्व विवाह के बंधन में बंधे इस नव दंपत्ति को विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने सेवा सेतु केंद्र में आधार कार्ड, विवाह के फोटो, शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया।

सेवा सेतु केंद्र के कर्मचारियों ने सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीयन कर आवेदन संबंधित विभाग को भेज दिया। विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसे नव दंपत्ति ने सेवा सेतु केंद्र से प्राप्त किया। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध रही।

फलित पुरेना ने बताया कि सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान रही। न कहीं भटकना पड़ा और न ही किसी प्रकार की परेशानी हुई। इससे समय, श्रम और पैसे तीनों की बचत हुई। एक ही स्थान पर आवेदन जमा हुआ, दस्तावेजों का पंजीयन हुआ और निर्धारित समय में प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया।

छू लो आसमान के 52 विद्यार्थियों ने नीट-यूजी 2026 में की सफलता हासिल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। दंतेवाड़ा जिले की आवासीय कोचिंग संस्था 'छू लो आसमान' के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। संस्था के बालूद और कारली केंद्रों के 158 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 52 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। इनमें 11 विद्यार्थियों का एमबीबीएस तथा 11 विद्यार्थियों का बीडीएस, बीएएमएस, पशु चिकित्सा सहित अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लगभग सुनिश्चित माना जा रहा है।

बालूद केंद्र से इस वर्ष 65 विद्यार्थियों ने नीट-यूजी परीक्षा दी,

जिनमें से 25 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की। इनमें 9 विद्यार्थियों ने 340 से अधिक अंक हासिल किए हैं, जिससे उनका एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लगभग सुनिश्चित माना जा रहा है। वहीं, 5 विद्यार्थियों का बीडीएस, बीएएमएस, पशु चिकित्सा सहित अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में चयन संभावित है।

इसी प्रकार कारली केंद्र से 93 विद्यार्थियों ने नीट-यूजी परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से 27 विद्यार्थी सफल रहे।

इनमें 2 विद्यार्थियों का एमबीबीएस तथा 6 विद्यार्थियों का बीडीएस, बीएएमएस और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लगभग सुनिश्चित माना जा रहा है।

'छू लो आसमान' संस्था के विद्यार्थियों की यह सफलता जिले में उपलब्ध कराई जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर कोचिंग सुविधाओं और विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। आवासीय कोचिंग व्यवस्था के माध्यम से जिले के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।

क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने नीट-यूजी 2026 में सफल सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पूरे जिले का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है।

प्रदेश में खेती-किसानी जोरों पर: राज्य में 33.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लक्ष्य का 69 प्रतिशत बोनी पूर्ण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश में मानसून के दस्तक के साथ ही खेती किसानी का कार्य जोरों पर हैं। राज्य में 22 जुलाई की स्थिति में राज्य के 33.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में लक्ष्य का 69 प्रतिशत बोनी हो चुकी है। इस खरीफसीजन में 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को खेती-किसानी में सहुलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों निर्देशित किए गए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने को कहा हैं। खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज का भण्डारण कर सतत निगरानी करने को कहा गया है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के किसानों को अब तक 9.22 लाख मीट्रिक टन खाद और 4.12 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मानसून की बौछारों के साथ शुरू हुए खेती-किसानी में बोनी का रकबा भी निरंतर बढ़ते जा रहा है। राज्य में अब तक 33.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों जैसे धान, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, मूंगफली, रामतिल आदि की बोनी हो चुकी है, जो लक्ष्य का 69 प्रतिशत है। इस खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों ने बताया कि 22 जुलाई सुबह तक की स्थिति में प्रदेश में अब तक 389.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1246.3 मिमी है। गौरतलब है कि औसत दर्ज वर्षा जिलों की आज तक की औसत वर्षा पिछले 10 वर्षों के आधार पर 421.5 मिमी. है। वहीं प्रतिवेदित समय तक आज हुई वर्षा 33.5 मिमी. है।

जरूरतमंद किसानों को 6633.71 करोड़ रूपये का निःशुल्क अल्पकालीन कृषि ऋण: अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को खेती-किसानी में सहूलियते हो इस उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्प कालीन कृषि ऋण उपलब्ध करा रहे है। चालू खरीफ सीजन 2026 के लिए 21 जुलाई की स्थिति में 6633.71 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 5560.34 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया गया था। इस वर्ष किसानों को 8800 करोड़ रूपए ऋण वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों को 4.12 लाख क्विंटल बीज वितरित

अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2026 के लिए बीज निगम द्वारा प्रदेश में 4.95 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध 4.70 लाख क्विंटल बीज का भंडारण कर अब तक 4.12 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो मांग का 83 प्रतिशत है। गत वर्ष इसी अवधि में 4.11 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया था। इसी प्रकार प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 14.57 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। उक्त भंडारण के विरूद्ध 9.22 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 59 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री के जनस्वास्थ्य विजन को मिली बड़ी सफलता

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनस्वास्थ्य विजन के तहत संचालित राष्ट्रव्यापी निःशुल्क एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले ने छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यू-विन प्रगतिशील रिपोर्ट के अनुसार जिले ने 100 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज कर प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व तथा जिला प्रशासन की सतत मॉनिटरिंग और प्रभावी रणनीति के चलते स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा मैदानी अमले के समन्वित प्रयासों से यह सफलता मिली। दूरस्थ और विशेष पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंच बनाकर पात्र किशोरियों का टीकाकरण सुनिश्चित किया गया।

खास खबर

नकली नोट से शराब खरीदने पहुंचा युवक गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा के अकलतरा पुलिस ने देशी शराब दुकान में नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 20 जुलाई को अकलतरा स्थित देशी मदिरा दुकान से सूचना मिली कि एक युवक नकली नोट देकर शराब खरीदने का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में आरोपी की पहचान सत्येन्द्र कुमार कुर्रे उर्फ सत्यम कुर्रे (30) निवासी दोमुहानी, थाना बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से 500 रुपये के चार संदिग्ध नोट बरामद किए गए। पुलिस ने बरामद नोटों की जांच स्टेट बैंक, अकलतरा में कराई, जहां चारों नोट नकली पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि सभी नोटों का सीरियल नंबर एक ही था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नकली नोट रायपुर से लाया था और उन्हें शराब दुकान में चलाने की कोशिश कर रहा था। अकलतरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 180 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

ट्रैक्टर पलटने से दो की मौत मामले में चालक गिरफ्तार हिर्री पुलिस ने भेजा जेल

बिलासपुर। हिर्री थाना पुलिस ने ट्रैक्टर दुर्घटना में दो लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, 21 जुलाई 2026 की सूचना मिली कि ग्राम मेड़पार-बाजार स्थित मोतीलाल जायसवाल के खेत में ट्रैक्टर पलटने से दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ अन्य लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक दामोदर मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू की। जांच के दौरान दुर्घटना में शामिल बिना नंबर के ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया गया। ट्रैक्टर चालक चन्द्रशेखर पटेल (26 वर्ष), निवासी मेड़पार-बाजार, थाना हिर्री, जिला बिलासपुर के खिलाफ जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281, 125(ए) एवं 105 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की।

स्कूटी से शराब तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। अवैध शराब का परिवहन एवं बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 144 पौवा देशी शराब, एक स्कूटी और मोबाइल फोन सहित 64,400 रुपये मूल्य की सामग्री जब्त की गई है। एक व्यक्ति सुजुकी एक्सेस स्कूटी से जुनवानी क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के लिए ले जा रहा है। सूचना पर स्मृतिनगर पुलिस ने परिया नाला, जुनवानी में घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोक लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मुकेश पाटिल बताया। तलाशी के दौरान उसके पास रखे बैग से 144 नग शोले मसाला देशी मदिरा बरामद हुई। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

उर्वरक व कीटनाशक के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, दो गोदाम सील, भारी मात्रा में सामग्री जब्त

मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर कार्रवाई, बिना लाइसेंस उर्वरक-कीटनाशक का कर रहे थे भंडारण और निर्माण

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदान समय पर उपलब्ध कराने तथा नकली एवं अमानक उर्वरक-कीटनाशकों के कारोबार पर प्रदेशभर में कृषि विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दुर्ग जिले में कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल ने ग्राम चिंगरी (अंडा) में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध अनुज्ञप्ति के उर्वरक एवं कीटनाशक का निर्माण, भंडारण और विक्रय किए जाने के मामले में दो गोदामों को सील कर भारी मात्रा में सामग्री जब्त की है।

उड़नदस्ता दल को ग्राम चिंगरी स्थित चन्द्राकर किराना स्टोर्स परिसर में अवैध रूप से जैव उत्प्रेरक एवं कीटनाशकों के निर्माण एवं भंडारण की सूचना प्राप्त हुई थी। निरीक्षण के दौरान गोदाम बंद मिला। गोदाम के किरायेदार वरुण त्रिपाठी को मौके पर बुलाकर निरीक्षण में सहयोग करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके असहयोगात्मक रवैये के कारण मकान मालिक, पंचों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर गोदाम का ताला खुलवाया गया।

निरीक्षण में मिला अवैध निर्माण व भंडारण का पूरा नेटवर्क

निरीक्षण के दौरान गोदाम में बिना लाइसेंस जैव उत्प्रेरक एवं कीटनाशकों के निर्माण के लिए कच्चा माल, तैयार उत्पाद, पैकिंग मशीनें तथा बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल मिला। जांच में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम एवं नियमों के अनेक प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। बिना वैध अनुज्ञप्ति के व्यवसाय, बिना मानक के उर्वरक निर्माण, निर्धारित अभिलेखों का संधारण नहीं करना, निरीक्षण में सहयोग नहीं करना तथा बिना स्रोत के कीटनाशकों का भंडारण जैसे गंभीर मामले सामने आए।

भारी मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक और मशीनरी जब्त

कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में जैव उत्प्रेरक, कीटनाशक, उर्वरक, रॉ मटेरियल, रसायनों से भरे ड्रम, पैकिंग एवं सीलिंग मशीनें तथा अन्य उपकरण जब्त किए गए। संपूर्ण सामग्री को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत जब्त कर गोदामों को सील किया गया है। कृषि विभाग ने संबंधित संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मामले में नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

उप संचालक कृषि संदीप भाई ने स्पष्ट कहा कि किसानों को खाद एवं कीटनाशकों की कृत्रिम कमी पैदा करने, कालाबाजारी करने, नकली अथवा अमानक कृषि आदानों का निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं एवं निर्माताओं के लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त किए जाएंगे तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं एवं सहकारी समितियों को निर्देशित किया है कि किसानों को निर्धारित दर पर ही उर्वरक उपलब्ध कराएं। अधिक मूल्य वसूली, कालाबाजारी अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खरीफ सीजन में प्रदेशभर में जारी रहेगा सघन अभियान

कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों एवं कीटनाशकों की उपलब्धता, गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसानों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं नकली, अमानक अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक या कीटनाशकों की बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी शिकायत तत्काल निकटतम कृषि विभाग कार्यालय में करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नकली कृषि आदानों, कालाबाजारी और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के विरुद्ध पूरे प्रदेश में इसी तरह की सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।

बस्तर का नटवरलाल: पुलिस को चकमा देकर 3 जेलों से 4 बार हो चुका था फरार, फिर गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

जगदलपुर। बस्तर में जेल प्रशासन और पुलिस के लिए सिरदर्द बने आदतन फरार अपराधी महेंद्र दीवान उर्फ नटवरलाल को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 25 मार्च को जगदलपुर केंद्रीय जेल की दीवार फांदकर फरार होने के करीब तीन महीने बाद कोतवाली पुलिस ने उसे नारायणपुर में घेराबंदी कर दबोच लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही बस्तर पुलिस ने लंबे समय से चल रही तलाश खत्म कर दी।

कोतवाली थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि महेंद्र दीवान की तलाश लगातार जारी थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर विशेष टीम नारायणपुर भेजी गई। पुलिस ने उसके ठिकाने की घेराबंदी कर बिना किसी मौका दिए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। महेंद्र दीवान (25), निवासी चितालंका कलारपारा, जिला दंतेवाड़ा, चोरी के मामलों का आदतन आरोपी है। उसके खिलाफ बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में चोरी के सात मामले दर्ज हैं।

लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान जेल तोड़कर भागने की घटनाएं हैं। यही वजह है कि पुलिस महकमे में उसे 'बस्तर का नटवरलाल' कहा जाता है।

25 मार्च की शाम महेंद्र ने फिल्मी अंदाज में पुरुष बैरक से निकलकर महिला बैरक के पास की अपेक्षाकृत छोटी दीवार को पार किया और जेल से फरार हो गया। कैदियों के शोर मचाने तक वह अंधेरे का फायदा उठाकर निकल चुका था। घटना के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे।

उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उसे रायपुर केंद्रीय जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। अब नारायणपुर से गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया है।

महेंद्र पहले दंतेवाड़ा और कांकेर जेल से फरार हो चुका है। एक बार इलाज के लिए महारानी अस्पताल (मेकाज) लाए जाने के दौरान भी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था, हालांकि तब उसे कुछ घंटों बाद पकड़ लिया गया था।

इन घटनाओं के बाद उसे हाई सिक्योरिटी मानी जाने वाली जगदलपुर केंद्रीय जेल में रखा गया था।

क्रेडिट-कार्ड से कैश अकाउंट में ट्रांसफर के नाम पर ठगी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर में इंस्टाग्राम पर दिखे एक विज्ञापन के जरिए क्रेडिट कार्ड से पैसे खाते में ट्रांसफर कराने का लालच एक व्यक्ति को भारी पड़ गया।

ठगों ने पहले 50 हजार रुपए जमा करवाए, फिर रकम लौटाने का झांसा देकर 20 हजार रुपए और ट्रांसफर करा लिए। कुल 70 हजार रुपए से अधिक की ठगी होने के बाद पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन और पुलिस से शिकायत की है। पीड़ित का नाम डूंडा निवासी अनिल कुल्हाड़िया (42) बताया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2026 को उनके इंस्टाग्राम आईडी पर fit_sush_model नाम के अकाउंट से एक विज्ञापन दिखाई दिया, जिसमें क्रेडिट कार्ड से सीधे बैंक खाते में रकम ट्रांसफर करने का दावा किया गया था। विज्ञापन पर भरोसा कर उन्होंने

50 हजार रुपए जमा कर दिए। इसके बाद ठगों ने व्हाट्सएप पर संपर्क कर भरोसा दिलाया कि 24 घंटे के भीतर पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।

बाद में आरोपियों ने तकनीकी कारण बताकर कहा कि पूरी रकम एक साथ ट्रांसफर नहीं हो सकती और आंशिक भुगतान की प्रक्रिया के नाम पर उनसे 20,500 रुपए और जमा करा लिए।

जब काफी इंतजार के बाद भी कोई रकम वापस नहीं मिली तो अनिल को अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद मुजगहन थाने पहुंचकर लिखित आवेदन सौंपा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले आकर्षक ऑफर, आसान लोन या क्रेडिट कार्ड से कैश ट्रांसफर जैसे विज्ञापनों के झांसे में न आएं।

लकड़ी के अवैध परिवहन पर वन विकास निगम की बड़ी कार्रवाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। लकड़ी के अवैध परिवहन पर वन विभाग लगातार सख्त छापेमार कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पिकअप, ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रकों से भारी मात्रा में अवैध साल, सागौन, खैर और सागौन की लकड़ी जब्त कर वाहन चालकों और तस्करों पर भारतीय वन अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, अतिक्रमण और उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार गश्त और निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में बिलासपुर जिले के कोटा परियोजना मंडल में वन अमले ने अवैध रूप से सागौन की लकड़ी का परिवहन करते हुए एक पिकअप और एक बाइक जब्त की है। मामले में चार आरोपियों के खिलाफ वन अपराध दर्ज किया गया है।

कोटा परियोजना मंडल, बिलासपुर के भैंसाझार परिक्षेत्र के कलमीटार बीट अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी./1586 से जोगीपुर-रतनपुर सड़क मार्ग पर गश्त के दौरान वन अमले ने एक महिंद्रा पिकअप वाहन में सागौन प्रजाति के 11 लट्ठे अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़े। जब्त लकड़ी की मात्रा 1.138 घन मीटर है। कार्रवाई के दौरान वन अमले ने महिंद्रा पिकअप वाहन क्रमांक 5582 और लीवो (होंडा) बाइक क्रमांक 3192 को जब्त कर अभिरक्षा में लिया। मामले में नीलकुमार घृतलहरे, ललित साहू, लालसिंह और दुर्गेश पाली के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम, 1927 की संबंधित धाराओं के तहत वन अपराध दर्ज किया गया है। प्रकरण क्रमांक 87/27 दिनांक 21 जुलाई 2026 को दर्ज किया गया।

नियमित गश्त से वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक द्वारा वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सभी परियोजना मंडलों में नियमित और रात्रिकालीन गश्त के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के पालन में वन अमले द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। नियमित गश्त और त्वरित कार्रवाई से वन क्षेत्रों में अवैध कटाई और लकड़ी के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है।

क्षेत्रीय महाप्रबंधक बिलासपुर अभिषेक सिंह और मंडल प्रबंधक कोटा परियोजना मंडल सत्यदेव शर्मा के मार्गदर्शन में परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी वैभव साहू के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई में सहायक परियोजना क्षेत्रपाल अश्वनी मेहरा, गोविंदा वर्मा और अरुण कुमार सिंह सहित क्षेत्ररक्षक एवं रोपण सुरक्षा श्रमिक शामिल रहे।

वन अपराध के विरुद्ध तत्परता और प्रभावी कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक प्रेम कुमार ने वन अमले को बधाई दी है। उन्होंने निगम के सभी वन क्षेत्रों में इसी तरह सतर्कता और तत्परता के साथ वन सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। वन सुरक्षा और संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका का उल्लेख उनके आगामी गोपनीय प्रतिवेदन में भी किया जाएगा।

चार युवकों को एक बाइक पर घूमना पड़ा भारी यातायात पुलिस ने काटा 4,500 का चालान

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बाइक पर चार सवार होकर सड़क पर चल रहे युवकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। भांठागांव चौक में तैनात प्रधान आरक्षक संतोष चंद्राकर ने चार युवकों को एक दोपहिया वाहन पर सवार देखा, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस उपायुक्त यातायात डॉ. अर्चना झा के निर्देश पर संबंधित युवकों को यातायात कार्यालय बुलाया गया। पूछताछ और सत्यापन के बाद वाहन क्रमांक 9849 के चालक नैतिक गवली के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 4/181, 5/180, 184 और 128/194 के तहत कार्रवाई करते हुए 4,500 का चालान किया गया।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, बालोद (छ.ग.)

निविदा क्र. 03/त.शा.(निविदा)/का.अ./लो.स्वा.यां.खण्ड/2026 बालोद, दिनांक : 21-07-2026

निविदा आमंत्रण सूचना (मैनुअल पद्धति)

मैनुअल निविदाएं ''प्रपत्र-ए'' में प्रतिशत दर पर नीचे उल्लेखित कार्य के लिये कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बालोद द्वारा के एकीकृत पंजीयन व्यवस्था ई-रजिस्ट्रेशन की **सक्षम श्रेणी** में पंजीकृत ठेकेदारों से आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण:-

नि.सू.क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू. लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य	अमानत राशि
03	बालोद जिले के विकासखण्ड डौंडी एवं डौण्डीलोहारा के विभिन्न ग्रामों में भूजल पुनर्भरण हेतु 12 नग इन्जेक्शन वेल निर्माण कार्य।	रु. 3.84 लाख	750/-	5,000.00

टीप:- संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन की जा सकती है।

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन जमा करने :- 10.08.2026 समय सायं 05:30 बजे तक की अंतिम तिथि

निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि :- 10.08.2026 समय सायं 05:30 बजे तक

स्पीड पोस्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि :- 13.08.2026 समय सायं 05:30 बजे तक

उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी दिनांक 21/07/2026 से एवं कार्यालयीन समय पर कार्यालय में देखे जा सकते है।

कार्यापालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बालोद
जिला - बालोद (छ.ग.)

जी-262702275/3

सब्जी से भरी पिकअप हादसे का शिकार, बिजली खंभे से टकराई, चालक घायल, 3 घंटे तक बिजली रही बंद

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे कनकी भाटा के पास सब्जी से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे और सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकरा गई। हादसे में पिकअप चालक घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बारिश के कारण सड़क पर फिसलन थी। वहीं, वाहन की रफ्तार भी तेज थी। कोरबा से बिलासपुर जा रही पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पहले बिजली के खंभे से टकराई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली का खंभा जड़ से टूटकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद पिकअप रेलिंग तोड़ते हुए उसमें जा घुसी। गनीमत रही कि पीछे आ रहे राहगीर और दोपहिया वाहन सवार हादसे की चपेट में नहीं आए। खंभा टूटने के बाद हाईटेंशन तार सड़क पर गिर गए थे। बिजली चालू होने के कारण राहगीरों के लिए खतरा बढ़ गया था। लोगों ने तुरंत विद्युत विभाग को इसकी सूचना दी।

सूचना मिलते ही विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के लिए क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। इसके बाद टूटे खंभे को हटाने और तारों की मरम्मत का काम शुरू किया गया।

पुलिस के अनुसार, चालक का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

जशपुर में 44 पशु, तस्करों से मुक्त कराए गए: 7 तस्कर गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुर। जशपुर जिले में गौ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के ऑपरेशन शंखनाद के तहत सोमवार को तपकरा थाना और मनोरा चौकी क्षेत्र में दो बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने कुल 37 गौवंश और 7 भैंसों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। तपकरा में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि मनोरा में पुलिस को देखकर तस्कर जंगल के रास्ते फरार हो गए।

पुलिस के मुताबिक, 21 जुलाई की सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी कि सड़वा जंगल के रास्ते 28 गौवंशों को झारखंड ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया और सभी गौवंश को सुरक्षित छुड़ा लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान जगन्नाथ खड़िया(41), गणेश राणा(30), रमेश बेहरा(29), कहरु बेहरा(35), मनोरंजन बेहरा (51) निवासी ग्राम चांपा डांड, थाना कुरडेग, जिला सिमडेगा (झारखंड), मोहन यादव (33) निवासी गहिरा दोहर, चौकी दोकड़ा, जिला जशपुर तथा मग दुम खान (25) निवासी उलूडीह, तलसरा, जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) के रूप में बताई। पशुओं के परिवहन से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 और 10 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

इसी दिन सुबह मनोरा चौकी पुलिस ने ग्राम इंदा घाट जंगल में दबिश देकर 9 गौवंश और 7 भैंसों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया। हालांकि पुलिस टीम को देखते ही तस्कर जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है।

महतारी वंदन योजना से माताओं और बहनों के जीवन में आया आत्मविश्वास और आर्थिक स्वावलंबन : मुख्यमंत्री साय

महिला सशक्तिकरण, रोजगार, पर्यटन, उद्योग और सुशासन के विजन को मुख्यमंत्री ने किया साझा, बस्तर में शांति, विकास और रोजगार का नया अध्याय शुरू

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित 'इमर्जिंग छत्तीसगढ़–सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण, बस्तर के विकास, रोजगार, उद्योग, पर्यटन, सुशासन और सामाजिक सुधारों पर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को विस्तार से रखा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ केवल एक राज्य नहीं, बल्कि हम सभी के लिए छत्तीसगढ़ महतारी है। यह माता कौशल्या की पावन जन्मभूमि और भगवान श्रीराम का ननिहाल है। भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च सम्मान देने की परंपरा रही है। उन्होंने वेदों का उल्लेख करते हुए कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का वास होता है।

महतारी वंदन योजना से महिलाओं के चेहरे पर लौटी मुस्कान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की लगभग 68 लाख 50 हजार विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपये सीधे उनके बैंक खातों में दिए जा रहे हैं। अब तक 29 किश्तों के माध्यम से लगभग 18 हजार 800 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में अंतरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब वे गांवों का दौरा करते हैं तो माताओं और बहनों के चेहरों पर इस योजना से आया आत्मविश्वास और संतोष स्पष्ट दिखाई देता है। बातचीत के दौरान माताएं और बहनें बताती हैं कि किसी ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है, किसी ने सिलाई मशीन खरीदकर रोजगार शुरू किया है तो किसी ने किराना या सब्जी की दुकान खोलकर आय बढ़ाई है। इससे माताएं और बहनें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार की निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।

सिंचाई, कृषि और पर्यटन से आत्मनिर्भर बनेगा बस्तर

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में इंद्रावती नदी पर देउरगांव एवं मटनार सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनसे लगभग 80 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी। उन्होंने कहा कि चित्रकोट जलप्रपात, कुटुमसर गुफाएं, अबूझमाड़ के विशाल वन तथा धुड़मारास जैसे गांव बस्तर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में होम-स्टे को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत पांच कमरों तक के होम-स्टे निर्माण के लिए ऋण और सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इमली, महुआ, हर्रा, बहेड़ा, सीताफल और औषधीय वनोपजों का मूल्य संवर्धन कर स्थानीय लोगों की आय बढ़ाई जा रही है। नेतानार जैसे गांवों में सेवा डेरा के माध्यम से महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई, पैकेजिंग तथा अन्य आजीविका आधारित प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। आईआईटी की टीम भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास का कार्य कर रही है।

धर्मांतरण के विरुद्ध कड़ा कानून लागू

मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण समाज के लिए गंभीर चुनौती है। विभिन्न राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 लागू किया गया है। इसके तहत धर्म परिवर्तन करने और करवाने वाले दोनों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रलोभन, दबाव अथवा छलपूर्वक धर्मांतरण करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पीएससी घोटाले की जांच और रोजगार पर सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच जारी है तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने विभिन्न विभागों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है तथा शीघ्र ही 5 हजार शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निजी निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया जा रहा है। पिछले डेढ़ वर्षों में राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

36 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत लगभग 36 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया तथा गंभीर रोगियों को बेहतर उपचार के लिए बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया। अधिकारी स्वयं दूरस्थ गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के दानसरा गांव की माताओं और बहनों ने महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि को एकत्र कर भगवान श्रीराम के मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि यह इस योजना का सबसे प्रेरक उदाहरण है कि महिलाएं इस राशि का उपयोग समाज और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी कर रही हैं।

30 लाख से अधिक महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2 लाख 86 हजार महिला स्व-सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे लगभग 30 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन्हें रेडी-टू-ईट कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है तथा ऋण एवं अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बस्तर में नक्सलवाद से विकास की ओर ऐतिहासिक परिवर्तन

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि चार-पांच दशकों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा बस्तर अब तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और स्थानीय जनता के सहयोग से बस्तर में शांति स्थापित हुई है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा कैंप स्थापित करने के साथ-साथ विकास की योजनाओं को भी समानांतर रूप से आगे बढ़ाया गया। पहले सुरक्षा शिविरों के पांच किलोमीटर दायरे तक योजनाओं का लाभ पहुंचता था, जिसे अब बढ़ाकर दस किलोमीटर तक किया गया है।

नियद नेल्ला नार से 500 से अधिक गांवों तक पहुंची सरकार

मुख्यमंत्री ने बताया कि नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत अब 500 से अधिक गांवों को जोड़ा जा चुका है। लगभग 17 विभागों की 40 से अधिक योजनाओं का लाभ इन गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। यहां लोगों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

समान नागरिक संहिता की दिशा में भी तेजी से कार्य

उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है तथा राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र तक इस दिशा में ठोस प्रगति हो।

महिलाओं ने साझा किए अपने अनुभव

बलौदाबाजार जिले की मीना देवांगन ने महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि योजना से प्राप्त राशि से उन्होंने चूड़ी का व्यवसाय शुरू किया है। वहीं सरोज ने कहा कि वे इस राशि से अपने बच्चे की स्कूल फीस का भुगतान कर रही हैं। दोनों महिलाओं ने कहा कि इस योजना ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री साय की पहलः स्वस्थ माताएं, स्वस्थ बच्चे और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए बनेगी समन्वित रणनीति

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मंत्रालय महानदी भवन में भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे ने शिष्टाचार भेंट की। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण उन्मूलन तथा बच्चों के समग्र विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा बच्चों के पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इन क्षेत्रों में स्थायी सुधार के लिए सभी विभागों के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वस्थ माताएं और स्वस्थ बच्चे ही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आदिम जाति विकास विभाग सहित सभी संबंधित विभाग यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से एक समन्वित और परिणामोन्मुख कार्ययोजना तैयार करें, जिससे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुपोषण में कमी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का प्रभाव तभी बढ़ेगा, जब विभिन्न विभाग साझा लक्ष्य और समन्वित कार्यप्रणाली के साथ काम करेंगे। उन्होंने अधिकारियों से ऐसी मल्टी-सेक्टोरल रणनीति तैयार करने को कहा, जिससे स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचे और बच्चों के पोषण स्तर में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हो।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुश्री सिंथिया मैककैफ्रे का शॉल एवं छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक 'नंदी' भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। वहीं सुश्री मैककैफ्रे ने भारत में यूनिसेफ के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी विशेष स्मारक डाक टिकट मुख्यमंत्री को भेंट किया। यूनिसेफ की भारत प्रतिनिधि सुश्री सिंथिया मैककैफ्रे ने मुख्यमंत्री का जय जोहार कहकर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और सरल-सहज लोगों का प्रदेश है।

उन्होंने बताया कि यूनिसेफ लंबे समय से राज्य सरकार के साथ मिलकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश के बच्चों का भविष्य अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ की प्रमुख सीमा कुमार, अनिल गुलाटी तथा डॉ. बाल पारितोष दास उपस्थित थे।

मल्हार में खुली छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की नई शाखा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक नगरी मल्हार के लिए बुधवार का दिन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया। यहां छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की 629वीं शाखा तथा बिलासपुर जिले की 37वीं शाखा का शुभारंभ किया गया। नई शाखा खुलने से अब मल्हार और आसपास के गांवों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए दूसरे शहरों या कस्बों का रुख नहीं करना पड़ेगा। किसानों, महिलाओं, युवाओं, स्वयं सहायता समूहों, छोटे व्यापारियों और आम ग्रामीणों को बचत, ऋण, सरकारी योजनाओं की राशि, पेंशन तथा डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। शाखा का उद्घाटन बैंक के अध्यक्ष विनोद कुमार अरोरा ने किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेश कुमार सिंह राजपूत, कॉर्पोरेट कार्यालय से निवास, वरिष्ठ प्रबंधक दिनेश कुमार चौहान, सामान्य बैंकिंग प्रभारी राहुल कुमार शर्मा, शाखा प्रबंधक धीरज कुमार, कार्यालय सहायक यश गुप्ता, शिक्षक शेष नारायण गुप्ता, अवधेश कुमार, लक्ष्मी वस्त्रालय के संचालक नरेन्द्र कुमार, सत्य राय सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

समारोह को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अरोरा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक सुलभ बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना बैंक की प्राथमिकता है। उन्होंने बैंक की विभिन्न बचत एवं ऋण योजनाओं, डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देते हुए कहा कि नई शाखा क्षेत्र के आर्थिक विकास और वित्तीय लेनदेन को नई गति देगी।

उन्होंने साइबर सुरक्षा पर भी विशेष जोर देते हुए लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें और किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक से सावधान रहें।

फिर दिखा राष्ट्रीय गौरव पक्षी सारस क्रेन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की आर्द्रभूमियों में राष्ट्रीय गौरव पक्षी और दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षी 'सारस क्रेन' का दिखना पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से बेहद सुखद खबर है। छत्तीसगढ़ में इन पक्षियों की संख्या बहुत कम बची है, इसलिए इनका किसी स्थानीय जलाशय या वेटलैंड में दिखाई देना एक महत्वपूर्ण घटना है। पक्षी 'सारस क्रेन' जीवनभर के लिए अपना एक ही साथी चुनते हैं। भारतीय संस्कृति में इन्हें प्रेम और अटूट संबंध का प्रतीक माना जाता है।

छत्तीसगढ़ में आर्द्रभूमि और पक्षी जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सरगुजा जिले से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। सरगुजा वनमंडल के लखनपुर परिक्षेत्र स्थित कुवांरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में सारस क्रेन के एक जोड़े का सफलतापूर्वक अवलोकन किया गया है। यह महत्वपूर्ण अवलोकन वनमंडलाधिकारी अभिषेक जोगावत के मार्गदर्शन में चल रही नियमित निगरानी के दौरान दर्ज किया गया।

क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग तकनीकी सहायक धनीराम और बीट गार्ड राजेंद्र खुजूर द्वारा की जा रही है। उनके प्रयासों से सारस क्रेन के जोड़े की यह महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की जा सकी। सारस क्रेन भारत के सबसे आकर्षक पक्षियों में से एक है और विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। किसी आर्द्रभूमि में इसकी उपस्थिति उस क्षेत्र के स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है। विशेष बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सारस क्रेन के प्रमाणित और नियमित अवलोकन वर्तमान में सरगुजा क्षेत्र से ही प्राप्त हो रहे हैं। इससे सरगुजा की आर्द्रभूमियों के संरक्षण महत्व को और मजबूती मिलती है।

वन विभाग ने स्थानीय नागरिकों, पक्षी प्रेमियों और प्रकृति संरक्षण से जुड़े लोगों से आर्द्रभूमियों एवं वन्यजीवों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। विभाग ने लोगों से ऐसे महत्वपूर्ण पक्षियों के अवलोकन की जानकारी वन विभाग को देने का आग्रह किया है, ताकि उनके संरक्षण और वैज्ञानिक अभिलेखीकरण को और मजबूत किया जा सके। कुवांरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में सारस क्रेन का यह अवलोकन सरगुजा की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति किए जा रहे प्रयासों की सफलता का महत्वपूर्ण प्रमाण है।

वैज्ञानिक अध्ययन और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड

कुवांरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में सारस क्रेन के जोड़े का अवलोकन राज्य की आर्द्रभूमि पक्षी विविधता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह रिकॉर्ड क्षेत्र की बेहतर पारिस्थितिक स्थिति और आर्द्रभूमि संरक्षण के सकारात्मक परिणामों को भी दर्शाता है। यह अवलोकन भविष्य में पक्षी विविधता के वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण योजनाओं और आर्द्रभूमि प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगा।

जनजातीय बालिकाओं के विकास का सशक्त माध्यम बनेगा शबरी वाचनालय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज वनवासी विकास समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा जनजातीय बालिकाओं में अध्ययन, ज्ञानार्जन एवं पठन-पाठन की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित शबरी वाचनालय का उद्घाटन किया। वाचनालय की स्थापना के लिए राज्यपाल द्वारा अपने स्वेच्छानुदान मद से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शबरी वाचनालय एक दूरदर्शी पहल है, जो जनजातीय बालिकाओं के लिए अध्ययन, चिंतन, आत्मविकास एवं व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त केंद्र बनेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां अध्ययन करने वाली बालिकाएं ज्ञान एवं शिक्षा के बल पर प्रतियोगी परीक्षाओं सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करेंगी। उनकी उपलब्धियां न केवल उनके परिवार, बल्कि समाज और राष्ट्र का गौरव भी बढ़ाएंगी।

उन्होंने कहा कि शबरी कन्या आश्रम वर्षों से जनजातीय बालिकाओं को केवल आश्रय और शिक्षा ही नहीं, बल्कि संस्कार, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रसेवा की भावना भी प्रदान कर रहा है। इसी का परिणाम है कि यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाली अनेक बालिकाएं आज शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन तथा समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण राज्य है। यहां की संस्कृति का संबंध रामायण काल की परंपराओं से है। उन्होंने कहा कि असम और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं में अनेक समानताएं हैं तथा दोनों राज्यों की सांस्कृतिक धारा भगवान श्रीराम से जुड़ी हुई है। ऐसे गौरवशाली सांस्कृतिक परिवेश का हिस्सा होना हम सभी के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय इंटरनेट और तकनीक का युग है। तेजी से बदलती जीवनशैली के बीच जीवन मूल्यों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। परिवार और समाज के प्रति संवेदनशीलता, संतोष और सकारात्मक सोच ही जीवन को सार्थक बनाती है। संतुष्ट व्यक्ति ही वास्तविक रूप से प्रसन्न रह सकता है। जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है, इसलिए इसके प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबद्ध वनवासी विकास समिति, छत्तीसगढ़ प्रांत विगत कई दशकों से जनजातीय समाज के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, स्वावलंबन एवं सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने का यह प्रयास वास्तव में प्रेरणादायी है।

समाज कल्याण विभाग की पहल बनी शुभम की नई ताकत, वॉकर मिला तो बढ़े आत्मविश्वास के साथ कदम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं तब सबसे अधिक सार्थक होती हैं, जब वे किसी जरूरतमंद के जीवन में वास्तविक बदलाव लेकर आती हैं। समाज कल्याण विभाग की ऐसी ही एक पहल ने मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम बांधाबाजार निवासी 90 प्रतिशत दिव्यांग शुभम कुमार गंधर्व के जीवन में नई उम्मीद का संचार किया है।

जन्म के कुछ समय बाद पोलियो से प्रभावित होने के कारण शुभम का बचपन अनेक कठिनाइयों के बीच बीता। सामान्य बच्चों की तरह चलना-फिरना उनके लिए संभव नहीं था और दैनिक कार्यों के लिए भी उन्हें परिवार के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता था। सीमित संसाधनों के बावजूद उनके माता-पिता ने कभी उनका हौसला टूटने नहीं दिया। उनकी माता ने अपने हाथों से लकड़ी का सहारा तैयार किया, जिसके सहारे शुभम धीरे-धीरे चलने का प्रयास करते रहे। इसी बीच समाज कल्याण विभाग की सहायक उपकरण योजना की जानकारी मिलने पर परिवार ने आवेदन किया। विभाग ने संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए शुभम को वॉकर उपलब्ध कराया। यह वॉकर उनके लिए केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर जीवन की नई शुरुआत बन गया। वॉकर मिलने के बाद शुभम अब पहले की तुलना में अधिक सहजता से चल-फिर पा रहे हैं। उनके आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वे अपने कई दैनिक कार्य स्वयं करने लगे हैं। परिवार के चेहरे पर भी संतोष और खुशी साफ दिखाई देती है। शुभम कहते हैं, वॉकर मिलने के बाद मेरा जीवन पहले से काफी आसान हो गया है। अब मुझे लगता है कि मैं भी अपने दम पर आगे बढ़ सकता हूं। शुभम के पिता अरुण कुमार गंधर्व ने समाज कल्याण विभाग और राज्य शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उनके बेटे के लिए किसी नई जिंदगी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि समय पर मिली इस मदद ने शुभम का आत्मविश्वास बढ़ाया है और पूरे परिवार को नई उम्मीद दी है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950